



वर्ष 52/ अंक 302/ पृष्ठ 8 / मूल्य ₹ 2.10

भोपाल, शनिवार 24 जून 2023 भोपाल से प्रकाशित

दैनिक



भोपाल की धड़कन

साध्य प्रकाश



रूस में विद्रोहियों का कई सैन्य ठिकानों पर का कब्जा, पुतिन का आरोप पीठ में छुरा धोया

dainiksandhyaprakash.in

अमेरिका में ही रिन्यू होंगे एच1-बी वीजा



मोदी काहिरा रवाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिन के इजिप्ट दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। चार दिन की अमेरिकी विजिट से मोदी सीधे मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचेंगे। मोदी को इस विजिट को बाइलेट्रल ट्रेड के हवाले से बेहद अहम माना जा रहा है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी इसी साल हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। दूसरे शब्दों में कहें तो 6 महीने में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को यह दूसरी मुलाकात होगी। मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक हजार साल पुरानी शिया मस्जिद अल-हाकिम भी जाएंगे।

प्रधामंत्री मोदी का भोपाल में रोड शो होगा: वीडी शर्मा

भोपाल। 27 जून को मध्यप्रदेश आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में रोड शो होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भोपाल में रोड शो करेंगे। हालांकि, इससे पहले पीएमओ ने रोड शो की मंजूरी नहीं दी थी। प्रधानमंत्री भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और बुध विस्तारक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। शर्मा ने बताया, रात्री दुर्गावती के बलिदान दिवस पर बालाघाट से पांच यात्राओं की शुरुआत हुई थी। 27 जून को पीएम मोदी इन पांचों यात्राओं का समापन करेंगे। प्रधानमंत्री जब भोपाल आएंगे, तो रोड शो भी होगा। भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे।

इन क्षेत्रों में सौगात देंगे पीएम मोदी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइडेल जिले में इन कार्ड का वितरण करेंगे। वहीं पूरे मध्यप्रदेश में आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम पंचायत स्तर पर आयोजित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों से लेकर रोजागर, उद्योग, शिक्षा ,स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों को सौगात दे सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा इसके 6 महीने के बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी दोनों चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभी से ताकत झोंक रही है। साथ ही हर क्षेत्र में सौगात की झंडी लगा रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणाम और लोकसभा चुनाव के भी काफी हद तक अच्छे आएंगे।

भारत लोकतंत्र की जननी और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन: मोदी

वॉशिंगटन। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यहां मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ रहा है। अमेरिका में एक भारत, श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूं। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगाए। इसके बाद पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन... गाया। इसके बाद मिलबेन ने पीएम के पैर छुए।

उन्होंने बताया कि अब अमेरिका में ही एच1-बी वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पीएम ने कहा, जैसे भोजन के बाद स्वीट डिश मिलती है, वैसे ही आपसे बात करना एक मीठी डिश थी जिसे मैं खाकर जा रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 3 दिनों में मैंने जो बाइडेन के साथ कई मुद्दों पर बात की। मैं अनुभव से कहता हूं कि बाइडेन एक सुलझे हुए अनुभवी नेता हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका, आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया, दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त होते देख रही है। भारत में गूगल का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। अब मेन इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश का यह सही समय है। दोनों देश एक बेहतर मजबूत देश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।



अफ्रीकी-अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने गाया भारतीय राष्ट्रगान, पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

अफ्रीकी-अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारत का राष्ट्रगान गाया, जिसे सुन सभी उत्साहित हो गए और वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। जन गण मन गाने के बाद मैरी ने पीएम मोदी का अभिवादन किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दिग्गज आईटी कंपनियां करेंगी भारत में बड़ा निवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में संपन्न अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद दुनिया की तीन दिग्गज आईटी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग की घोषणा की है। पीएम के साथ आईटी कंपनियों के दिग्गजों की बैठक के दौरान एपल के टिम कुक, फ्लेक्स को सीईओ रेवती अद्वैती, ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, एफएमसी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क डगलस, माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई मौजूद थे। अमेजन ने अगले सात साल में भारत में अतिरिक्त 15 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारत में कंपनी का कुल निवेश 26 अरब डॉलर हो जाएगा, वहीं गूगल ने कहा है कि वह गुजरात में अपना वैश्विक फिन्टेक ऑपरेशन सेंटर खोलेगा।



शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया



श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। शहर के ऐतिहासिक लाल चौक से पास प्रताप पार्क में यह स्तंभ बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, शाह वरिष्ठ राज-नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करके वे दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां आज मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई है। अपनी यात्रा के पहले दिन शुक्रवार को शाह ने सांबा जिले में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी समेत कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को गोल्डन हेल्थ कार्ड भी सौंपा। उन्होंने राजौरी हमले के विकटिम्स से भी मुलाकात की।



प्रदेश कांग्रेस ने आज राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया। भोपाल में धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।



पटना में विपक्षी एकता नहीं, राहुल की शादी का मुख्य मुद्दा रहा: शिवराज



गवालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पटना में सारे विपक्षी इकट्ठा हुए और वहां भी विपक्षी एकता नहीं बल्कि मुख्य मुद्दा राहुल गांधी की शादी रहा। बैठक के बाहर लालू यादव जी बता रहे हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो। तुम शादी कर लो दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाको वो दूल्हा कौन है, बारात कौन है। इसका ठिकाना ही नहीं है। ग्वालियर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा- जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पर आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि सब एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काठ की हांडी बार-बार थोड़ी ना चढ़ती है। कितनी भी एकता कर ले कुछ भी नहीं होने वाला। **बेहटा पहुंचे:** प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पाल समाज के सम्मेलन में भाग लेने के लिए बेहटा गांव पहुंच गए हैं। कार्यक्रम में पहुंचने पर उन्होंने कन्या पूजन किया। साथ ही लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रभारी मंत्री सहित अन्य मंत्रीगण व विधायक मौजूद थे।

आपने शब्दों की मर्यादा तार-तार की: कमलनाथ



मंडला। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने एक बार फिर राजनीति में शब्दों की मर्यादा तार-तार कर दी है। विपक्ष को सांप, मेंढक और बंदर कहा। पिछले कई दिन से आप रह-रह कर अपशब्दों और स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी यही भाषा और यही भावना जनता में आपके प्रति नफरत पैदा कर रही है। आप जब हमें सांप कहेंगे तो जनता हमें भगवान शिव का कंठहार समझेगी। जब आप हमें बंदर कहेंगे तो जनता हमें भगवान राम की वह वानर सेना समझेगी जिसने रावण की पाप की लंका ध्वस्त कर दी थी। मंडला में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा- मंडला जिला हमेशा मेरे हृदय के करीब रहा है परंतु आज देखकर दुख होता है कि मंडला जिला आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन की राजधानी बन गया है। मंडला की जनता शिवराज सिंह चौहान की सैकड़ों झूठी घोषणाओं की गवाह है, उदाहरण के तौर पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा

शिवराज जी कर गए थे लेकिन मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था।

उन्होंने कहा- केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार में देश में सबसे आगे हैं, आज प्रदेश में शिव राज नहीं भ्रष्ट राज है , नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है पैसे दो और काम लो हाल ही में हुए महाकाल लोक निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ खोखली सरकार द्वारा बनाई गई खोखली मूर्तियां। 18 वर्षों में 22000 घोषणाएँ अधूरी है आज मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि वह इस कलाकारी की राजनीति को भलीभांति समझ रहे हैं।

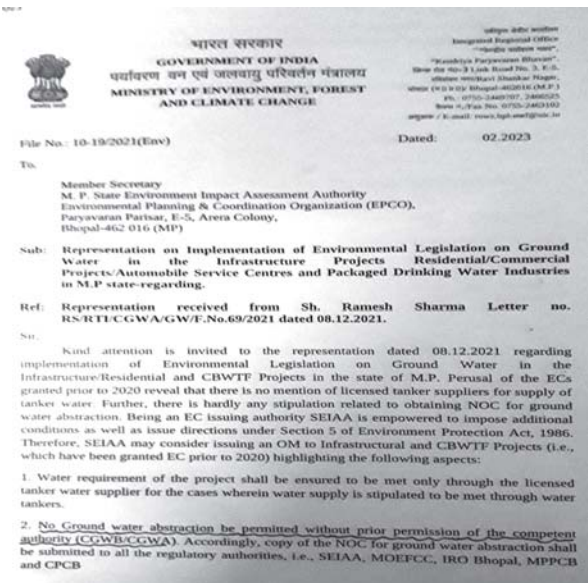
अवैध भूजल निष्कर्षण पर कार्रवाई, मंत्रालय के महत्वपूर्ण निर्देश जारी



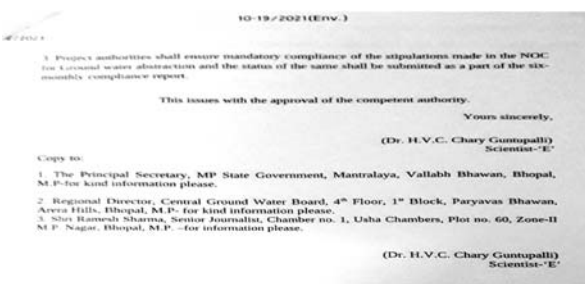
रमेश शर्मा
भोपाल। अवैध रूप से यानी बिना केंद्रीय भूजल मंडल से अनुमति लिए बगैर वर्षों से भूजल (ग्राउंड वाटर) निकालने वाले उद्योगों पर मप्र और छग ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी हो। ओपन आई न्यूज द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किए गए रिपोर्टेशन पर केंद्रीय भूजल मंडल भोपाल तथा रायपुर ने अच्छी खासी कार्रवाई की पहल की है जिसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।

शायद ये बात कम लोगों को ही मालूम होगी कि पिछले साल यानी 2022 को विश्व जल दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी ग्राउंड वाटर- मेकिंग द इ न व ज बी ब ल , विजीबल। मगर मप्र और छग में इस थीम पर अमल नहीं हो रहा था। इस मामले को प्रकाश में लाकर देश के शीर्ष अधिकारियों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को एक प्रस्तुतिकरण

सिआ ने भूजल निष्कर्षण संबंधी सभी बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी, किया है उसकी प्रतियां सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को दी गई हैं। अगर इसके बाद में भूजल के अवैध निष्कर्षण पर रोक नहीं लगती है तो एक्ट के मुताबिक जिम्मेदार लोगों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए।



भेजा गया, साथ ही आर्टीआई के तहत दस्तावेज प्राप्त किए गए। उच्चस्तर पर प्रेषित दस्तावेजों के आधार पर मप्र तथा छग ने उस्ताहजनक रुप से कार्य करना



शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कार्रवाई- दस्तावेज बताते हैं कि केंद्रीय भूजल मंडल रायपुर ने इस वर्ष यानी मार्च 2023 तक 99 उद्योगों को शोकांज नोटिस जारी किया है, जिसमें से रायपुर जिले में 69, बलोदा बाजार में 1, बस्तर में 2, बिलासपुर में 10, दुर्ग में 3, गरियाबंद में 1, जांजगीर चांपा में 5, जशपुर में 1, कोरिया में 1, महासमुंद में 3, रायगढ़ में 2 और सरगुजा में 11 इन नोटिसों की कॉपियां संबंधित जिला कलेक्टरों को भी भेजी गई हैं। हालांकि मिले आंकड़े उतने संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि छग में अभी भी कई उद्योग ऐसे हैं जिनके बारे में बोर्ड को संज्ञान लेना है। मप्र में कार्रवाई- मप्र शोकांज नोटिस देने में काफी आगे है। यहाँ 18 हजार के आसपास नोटिस के दिए गए हैं, जिसमें नवीन आवेदन भी शामिल किए गए हैं। अच्छी बात है कि यहां अनापत्ति प्रमाण पत्र भी उद्योगों द्वारा लिए जा रहे हैं। तेजी से होने वाली कार्रवाई अपेक्षित- यद्यपि इन दोनों राज्यों में भूजल

एक्ट के मुताबिक जिला कलेक्टर को अवैध बोरेवल सील करने का अधिकार दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार है, मगर सबसे पहले सभी जिम्मेदारों को गंभीर होने की जरूरत है।

उद्योग भूजल का उत्खनन बिना अनुमति के कर रहे हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 05 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। मगर पिछले दो तीन वर्षों से एक भी प्रकरण विभाग द्वारा पर्यावरण क्षति वसूलने को लेकर दर्ज नहीं किया गया। इसके पीछे मात्र एक कारण है कि जिम्मेदार अधिकारी कचहरी के कामकाज में उलझना नहीं चाहते हैं। शोकांज नोटिस जारी कर औपचारिकताएं पूरी की जा रही क्योंकि जो सक्षम तथा विधि सम्मत उद्योग चला रहे हैं वो तो एनओसी के लिए आवेदन देकर प्रक्रिया पूरी भी कर देते हैं, मगर अधिकांश तो ऐसे हैं जो नोटिस मिलने पर भी गंभीर नहीं होते हैं। ऐसे उद्योगपतियों का कहना है कि उन्हें ग्राउंड वॉटर की एनओसी लेने की प्रक्रिया में सलाहकार की मदद लेनी पड़ती है जो एक भारी भरकम रकम बतौर कन्सल्टेंसी मांगते हैं। इसमें कुछ सच्चाई भी है क्योंकि

-शेष पेज 8 पर

डॉ. मुखर्जी के बलिदान दिवस पर 26 युवाओं ने किया रक्तदान

युवाओं ने रक्तदान कर रक्त से धारा 370 का नक्शा और डॉ. मुखर्जी का चित्र बनाकर किया मोदी सरकार का धन्यवाद

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

गुरुनानक मंडल द्वारा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर शहीद गेट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया , रक्तदान शिविर में 26 युवा साथियों ने रक्तदान किया साथ ही अपने रक्त से धारा 370 का नक्शा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र बनाकर धारा 370 का सपना हुआ साकार धन्यवाद मोदी सरकार का संदेश लिखकर मोदी जी, अमित शाह जी को कोरियर द्वारा भेज धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर गुरुनानक मंडल अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। वे पहले व्यक्ति थे,

जो भारत की एकता तथा एकीकरण के लिए शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रहमंत्री अमित शाह के साहसिक निर्णय से राज्य का युवा वर्ग जम्मू कश्मीर को नेतृत्व देने के लिए स्वतंत्र हो गया हैं। यह मोदी सरकार की अप्रतिम इच्छाशक्ति का परिणाम हैं। भगवानदास ढलिया ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35-ए का हटाया जाना डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष राकेश कुकरेजा, नरेंद्र ठाकुर, संदीप कल्याण, शुभम श्रीवास, यतिन मकवाना, सुनील नीलकंठ,विष्णु राजपूत, निक्की ठाकुर,चंदू यादव, सिद्धार्थ जैन सहित बड़ी संख्या में युवा साथी उपस्थित थे



मकान बेचकर करोड़ों की रकम पाने बेटी कर रही थी माता-पिता को प्रताड़ित

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

राजधानी भोपाल में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटी अपने मां-बाप और मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई के लिये उनपर कहर बरपा रही थी। कलयुगी बेटी अपने पति से अलग होकर अपने बेटे के साथ मां-बाप के पास उनके ही घर में रह रही है, और माता-पिता पर मकान बेचकर पैसा उन्हें देने का दबाव बना रही थी। उसकी हरकतें जब पिता ने इंकार किया तब बेटी ने उन्हे यातनाएं देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं आरोपी बेटी का बेटा भी बुजुर्ग दंपति और उनके मानसिक विक्षिप्त बेटे को प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि बुजुर्ग मां-पिता और मानसिक विक्षिप्त भाई को बीते चार महिनो से कमरे में बंधक बनाकर रखते हुए रोजाना प्रताड़ित किया जा रहा था। कमरे का ताला केवल खाना देने के लिये खोला जाता था,

उसमें भी बेटी मां-पिता को बचा हुआ खाना देती थी। किसी भी बात का विरोध करने पर बेटी निधि सक्सेना अपने बेटे निखिल के साथ उन्हें बेल्ड, बेट या जो भी चीज हाथ में आये उससे मारपीट कर देती थी। बेटी जैसे शब्द को कलंकित करने वाली इस घटना में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अरेंरा कालोनी के मकान नंबर ई 7/72 में रहने वाले 80 वर्षीय सीएस सक्सेना एसबीआई से चीफ मैनेजर पद से रिटायर्ड अधिकारी हैं। घर में उनकी पत्नी कनक सक्सेना और मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटा विकी सक्सेना भी साथ रहता है। उनकी बेटी निधि की शादी भारतीय सेना के एक कर्नल से हुई थी। बाद में पति से तलाक होने के बाद निधि बेटे के साथ मां-पिता के पास आकर रहने लगी। सीएस सक्सेना एक हादसे के बाद चलने लायक नहीं रहे और बेड रेस्ट पर हैं। इस दौरान बेटी निधि सक्सेना और उसके बेटे निखिल सक्सेना ने

जबरन घर पर कब्जा कर लिया। बीते चार महिनों से निधि ने अपने पिता सीएस सक्सेना, मां कनक सक्सेना और मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई विकी सक्सेना को मकान की पहली फ्लोर के एक कमरे में बंधक बनाकर कर रखा था। उन्हें बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। केवल खाना देने के लिये कमरे का ताला खोला जाता था। बेटी उन्हें बचा हुआ खाना खाने के लिये देती थी। किसी जरूरत के लिये बाहर निकलने या अन्य जरूरत के सामान मांगने पर निधि रॉड-डंडे तथा क्रिकेट बेट से उन्हें पीटती थी। जब माता-पिता अधिक विरोध करते तब निधि का बेटा निखिल सक्सेना भी दंपति के साथ बेल्ड और बेट से पीटा था। यह भी आरोप है कि बेटी ने सक्सेना के अकाउंट का एटीएम भी अपने पास रखा है। और उनकी पेंशन के खाते से पूरी रकम निकालकर हड़प लेती है, और मां-पिता को उनकी दवा तक का पैसा नहीं देती। बेटी निधि

उन पर दबाव बना रही थी, कि मकान बेचकर करोड़ो की रकम उसे दे दें। लेकिन उसकी करतूते देखकर उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्हें उम्मीद थी रकम लेने के बाद उनकी बेटी उन्हें उनकी पत्नि और मानसिक रोगी बेटे को दर-दर की ठोकरें खाने के लिये छोड़ देगी। वहीं जब सक्सेना काफी समय से नजर नहीं आये तो पड़ोसी ने बेटी निधि उनके संबंध में पूछा, लेकिन निधि माता-पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं देती थी। तब एक पड़ोसी ने संदेह होने पर हबीबगंज पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही हरकत में आते हुए सीएस सक्सेना के घर जा पहुंची। पुलिस ने निधि और उसके बेटे से पूछताछ की तो वो कोई जानकारी देने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उपर के कमरे में ताला खुलवाया तो वहां वृद्ध सीएस सक्सेना घबराए बिस्तर पर लेटे हुए मिले।

बेटियों व महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करना भी एक अपराध

भोपाल/ हरदा / टिमरनी/ खंडवा। हमारे समाज में आज भी देखा जा रहा है कि महिलाओं व बेटियों को दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता है उन्हें परेशान किया जाता है उन्हें तन मन से भी प्रताड़ित किया जाता है जो कि अत्यंत अमानवीय घटना होती है जो कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना एक गुनाह है अपराध के समान है दहेज प्रथा पहले से होती आ रही है परंतु इस पर कोई रोक नहीं है यह बात पत्रकार मित्रों से चर्चा करते हुए समाजसेवी प्रोफेसर अर्पित गुर्जर जी ने समाज में कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर उन्होंने चर्चा की लोक मनमाने तरीके से दहेज लेते हैं और देते भी हैं जैसे रिश्तत लेना और देना दोनों पाप है उसी प्रकार दहेज लेना और देना दोनों पाप ही है दहेज के लिए इतना परेशान करना बेटियों व महिलाओं को मारना पीटना बहुत चलता है गांव हो या शहर दोनों में ही दहेज के लालची बहुत बढ़ गए हैं दहेज के लिए डिमांड चलती है गांव में दहेज प्रथा भी एक कु – प्रथा है यह प्रथा हमारे समाज के लिए काफी बेहद शर्मनाक है इस पर रोक होनी चाहिए ऐसे ही हाल में घटना हरदा जिले की टिमरनी तहसील के रहट गांव थाना क्षेत्र की है वहां हाल ही में हुई शादीशुदा जोड़े में दहेज के लालची पनपने लगे वहां बहु को इतना परेशान किया इतना प्रताड़ित किया कि वह परेशान हो गई उसकी जान चली गई यह घटना बहुत ही शर्मनाक शर्मशार अमानवीय और निंदा हारक है ऐसी दहेज प्रथा को लेकर एक घटना हुई कि उसे मौत के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया पीड़ित बहु को इन लालची लोगों के परेशान करने पर उसकी जान ले ली गई सर्वप्रथम दहेज लेना एवं देना दोनों गलत है ना जाने कितनी बेटियां महिलाएं बहुओं को अपनी जान देनी पड़ जाती है उन्हें मारा जाता है कई कई प्रकार से प्रताड़ित करते हैं कई बार उनकी जान ले लेते हैं मेरा यह मानना है कि बेटी महिलाओं को इन जैसे लालची लोगों को नजदीकी थाना क्षेत्र में शिकायत करें परंतु यह भी ध्यान रखें अगर दहेज प्रथा के लिए सच में परेशान करते हैं प्रताड़ित करते हैं तो जरूर शिकायत करें और इसका गलत फायदा उठाकर किसी को परेशान भी ना करें और आजकल यह भी सत्य है कि शायदियों में फिजूलखर्ची बहुत बढ़ गया है लोग अलग-अलग ढंग से शायदियों में पैसे खर्च करते हैं आजकल शायियां सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है जहां एक बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं पर जमाने के दिखावे के कारण उन्हें भी इधर-उधर से पैसे लेकर शादी करनी पड़ती है फिर भी दहेज के लालची लोग भी हमारे समाज में रहते हैं जो बहु एवं उसके माहिए और जो ऐसे लालची लोग लोग हैं उन्हें सजा मिलनी देश में आज भी लोगों के मन में दहेज प्रथा का चलन चलता है लोग बिना ढरे गर्व से अपने बेटे की कीमत लगाकर शादी में दहेज की डिमांड करते हैं कई बार देखा गया है कि शादी से पहले दहेज ना मिलने पर लोग शादी करने से इंकार कर देते हैं दहेज प्रथा एक कुप्रथा है उसको कुप्रथा के रूप में माना जाता है ऐसी प्रथा हमारे देश समाज से मुक्त कर देनी चाहिए दहेज प्रथा को मुक्त करने के लिए हमारे देश के हमारे सारे समाज के लोगों को आगे होना पड़ेगा और हमारे समाज से दहेज प्रथा मुक्त करना चाहिए और जो ऐसे लालची लोग लोग हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए सच में इन लालची लोगों को सजा मिले जिन्होंने ऐसी प्रथा को लेकर अपने घर की बेटी महिलाओं को प्रताड़ित किया है परंतु कई बार ऐसा भी देखा जाता है जानबूझकर भी आजकल ऐसे केस में अपने सेसुराल वालों को फंसा देते हैं पर यह गलत है कभी भी ऐसे गलत केस में ना फसाए



पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का जन्मदिन मनाया

भोपाल। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे इस अवसर पर महामंत्री नगर मंडल गोविंद कन्हारे एमआईसी सदस्य जगदीश यादव चेतन पाटीदार मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति महापौर मालती राय नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी नंदू सांऐसे सहित बड़ी संख्या में शुभचिंतकों और प्रशंसकों ने शुभकामनाएं दी।

नवीन महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ कार्यक्रम

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता ने योग द्वारा होने वाले शारीरिक विकास पर ध्यान देते हुये

समाज में अपना महत्वपूर्ण सहयोग कराने हेतु विद्यार्थियों को इसके होने वाले फायदे से अवगत कराया।

साथ ही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ शोभना जैन द्वारा विद्यार्थियों को योग के द्वारा हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी प्रदान

की गई। कार्यक्रम के सफल संचालन में सोमेश राठौर (अतिथि विद्वान) ले आराधना धुर्वे एन.सी.सी आफिसर महेश चौधरी तथा महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉ कृष्णा सिंह एवं डॉ मुस्कान सोलंकी, सीमा राजपूत सुलक्षणा दूबे एवं समस्त स्टॉफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

आईआईएसईआर ने नवाचार, डिजाइन और उद्यमिता को बढ़ावा देने किया बूटकैप का आयोजन

भोपाल। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा 22 जून से 26 जून तक नवाचार, डिजाइन और उद्यमिता (आईडीई) पर पांच दिवसीय आवासीय बूटकैप कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसका आयोजन ऑल इंडिया कार्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और शिक्षा मंत्रालय के इन्वेषन सेल (एमआईसी) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

बूटकैप के इस पांच दिवसीय आयोजन के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र और संकाय के सदस्य गहन प्रयोगात्मक शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसमें डिजाइन सोच, उत्पाद डिजाइन, यंत्रिकी विज्ञान, व्यापार मॉडलिंग और उद्यम योजना पर गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद मेंट्रिंग और पिचिंग का दौर भी होगा। पुणे के सीआईपी में आयोजित इस



बूटकैप कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने आयोजन केंद्रों के सभी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान बोलते हुए माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, वर्तमान समय में दुनिया तेजी से बदल रही है ऐसे माहौल में हाल के वर्षों के दौरान भारत ने भी नवाचार और विकास के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति

हासिल की है। अब अंग्रेजी में बोलना ही प्रतिभा का एकमात्र पैमाना नहीं है बल्कि भारत में कई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी में निपुण नहीं हैं इसके बावजूद वह बेहतर कर रहे हैं। अब विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालयों की क्षमताओं को समझकर उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के विकास में ये युवा नवाचारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एआईसीटीई के उप निदेशक डॉ. निखिल कांतने कहा,आजहम यहां एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे भावी नवाचारकों और उद्यमियों की आकांक्षाओं को एक विशेष आकार देगा।

बारिश में कहीं भी नालों का बहाव अवरूद्ध न हो: महापौर



सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व इम्पेनल्ड एनजीओ की बैठक में दिए निर्देश

महापौर मालती राय ने निर्देशित किया है कि शहर के सभी नालों की बेहतर ढंग से सफाई सुनिश्चित की जाए और वर्षा ऋतु में कहीं भी नालों का बहाव अवरूद्ध न हो। महापौर श्रीमती राय ने उक्त निर्देश निगम के स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अधिकारियों को स्वच्छता संबंधी कार्यों के संलग्न इम्पेनल्ड एन.जी.ओ की बैठक में दिए। महापौर श्रीमती राय ने साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त करने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती राय ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर शहर में योजनाबद्ध तरीके से सफाई कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

महापौर श्रीमती मालती राय ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व इम्पेनल्ड एन.जी.ओ की बैठक आहूत कर साफ-सफाई व्यवस्था, वर्षा पूर्व नालों की सफाई व स्वच्छता में समन्वय हेतु प्रत्येक वार्ड में एन.जी.ओ की तैनाती की समीक्षा की। महापौर श्रीमती राय ने साफ सफाई व्यवस्था सहित स्वच्छता की गतिविधियों, कचरा पृथक्कीकरण, परिवहन, निष्पादन को और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने, स्वच्छता की गतिविधियों में

सहयोग हेतु नागरिकों को भी प्रेरित करने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती राय ने वर्षा पूर्व नालों की सफाई के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की और नालों की सफाई निरंतर बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने और शहर में वर्षा के दौरान कहीं भी नाला-नालियों का बहाव को अवरूद्ध न होने देने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती राय ने जलभराव के संभावित क्षेत्रों के नालों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए।

महापौर श्रीमती राय ने स्वच्छता से संलग्न एन.जी.ओ. से प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता में समन्वय सहित अन्य कार्यों की भी जानकारी प्राप्त की। महापौर श्रीमती राय ने निर्देशित किया कि वार्डों में स्वच्छता संबंधी कार्यों की आवश्यकतानुसार एन.जी.ओ अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर स्वच्छता संबंधी कार्यों को बेहतर ढंग से सम्पादित करें। बैठक में महापौर परिषद के सदस्य श्री आर.के.सिंह बघेल के अलावा प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारीगण व इम्पेनल्ड एन.जी.ओ के प्रतिनिधि मौजूद थे।

चिल्ड्रेन्स होप इंडिया गर्ल्स स्कूल में शिक्षण सामग्री और गणवेश का वितरण

संत हिरदाराम नगर।

शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित चिल्ड्रेन्स होप इंडिया गर्ल्स स्कूल गाँधी नगर में नव युवक परिषद् द्वारा शिक्षण सामग्री और विद्यालय गणवेश का छात्राओं को वितरण किया गया। इस अवसर पर शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसायटी के सचिव ए.सी. साधवानी ने छात्राओं से कहा कि पढ़ाई ही एक मात्र जरिया है जिससे हर कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस अवसर पर संस्था के अकादमिक निदेशक गोपाल गिरधानी, नव युवक परिषद के महासचिव थावर वरलानी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है संत नगर की सामाजिक संस्था नवयुवक परिषद द्वारा निर्धन एवं मेधावी छात्राओं को गोद लेकर उनकी पढ़ाई-लिखाई का पूरा खर्च दान-दाताओं के सहयोग से किया जाता है। इस अवसर पर



गोपाल गिरधानी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए मेहनत व लगन के साथ अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अपने आप को पढ़-लिखकर इतना योग्य बनाइये कि भविष्य में आप भी इसी तरह दूसरी की सेवा व सहायता कर सकें। ऐसे बच्चे जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ने से वंचित रह जाते हैं आप उनकी सहायता कर सकें यदि हम राख

रॉयल रेस्पेक्ट के आकर्षक जायके का आनंद ले

भोपाल । खेमानी ग्रुप, जॉकि लीकर इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम है, ने मध्य प्रदेश में अपनी नई प्रीमियम व्हिस्की 'रॉयल रेस्पेक्ट' को लॉन्च किया है। भारत के मध्य भाग के रूप में लोकप्रिय, एमपी में रॉयल रेस्पेक्ट प्रीमियम व्हिस्की का लॉन्च दर्शाता है कि ब्रांड को क्वालिटी स्पिरिट्स के लिए राज्य की पसंद एवं सराहना की पूरी पहचान है। इस व्हिस्की में परंपरा एवं नवाचार के सार को समेटा गया है। पूरे राज्य में व्हिस्की के कद्रदानों को आखिरकार व्हिस्की का एक शानदार और बेजोड़ अनुभव लेने का मौका मिलेगा। रॉयल रेस्पेक्ट प्रीमियम व्हिस्की एक असाधारण मिश्रण है जिसे सबसे बेहतरीन स्कॉच मॉल्ट और भारतीय अनाज से बनी स्पिरिट्स को मिलाकर खास तरीके से तैयार किया जाता है, इस अनोखे फ्यूजन् से एक ऐसी व्हिस्की बनती है जिसमें विलासिता के साथ-साथ सॉफिस्टिकेशन भी होता है। प्रत्येक चूँट असली व्हिस्की के पाँच तत्वों के सुसंगत मिलन को प्रस्तुत करता है यानी इस व्हिस्की में स्मूदनेस, फ्लेवर, बॉडी, मधुरता (मेलोनेस) और उत्कृष्टता सब कुछ मौजूद है।

अमेजन प्राइम के फायदों का गुलदस्ता मध्य प्रदेश के ग्राहकों के बीच लगातार बांट रहा है खुशियां

भोपाल। अमेजन प्राइम अपने ग्राहकों को खरीदारी से लेकर मनोरंजन जैसे कई बेजोड़ फायदे प्रदान करता है। इसी के साथ ही अमेजन प्राइम ने हमेशा से ही ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने, उन्हें अधिक से अधिक विकल्प प्रदान करने और प्रत्येक ग्राहक के जीवन में %ज्यादा से ज्यादा खुशियां% भरने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के मेट्रो शहरों से लेकर बालाघाट, बुरहानपुर, देवास, गुना, मंदसौर, पन्ना और रीवा जैसे छोटे शहरों तक, प्राइम ने भारत के 99.5ब पिन कोड में सेलर्स और छोटे कारोबारियों को सशक्त बना रहा है। इसी के साथ ही अमेजन, देश भर में मौजूद अपने मैम्बर्स के लिए शॉपिंग, मनोरंजन और बचत का एक खास मिश्रण पेश करता है। 2016 में लॉन्च होने के बाद से, अमेजन प्राइम अपने सदस्यों की बलतीली जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए अपने लाभों के गुलदस्ते को लगातार बढ़ा बनाता जा रहा है। अमेजन प्राइम की एक मैम्बरशिप में सदस्यों को ढेरों लाभ मिलते हैं। आज अमेजन प्राइम, अपने मैम्बर्स को 40 लाख से अधिक प्रोडक्ट पर अनलिमिटेड मुफ्त वन डे डिलीवरी का लाभ प्रदान करता है।

सप्ताद की य

विपक्षी एकता का पटना राग...

लंबे समय से चली आ रही जद्दोजहद के बाद आखिरकार पटना में अधिकांश विपक्षी नेता एकजुट हुए और उनके बीच भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर प्राथमिक सहमति बन गई है। हालाँकि तेलंगाना वाले केसीआर, उड़ीसा वाले नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस जगनमोहन रेड्डी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लगभग सभी दल बैठक में मौजूद रहे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने पर हम सब सहमत हो गए हैं। सीटों के बँटवारे के लिए अगली बैठक शिमला में होगी। सभी नेताओं ने माना कि हम सब के बीच भी छोटे- मोटे मतभेद आरंगे, लेकिन चूँकि यह विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए हमें हर हाल में एक साथ बने रहना होगा। एक दिन पहले बैठक में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो शर्त रखी थी, उसे मान लिया गया। सभी दलों ने कांग्रेस से अपील की कि वह दिल्ली के अध्यादेश मामले में आप पार्टी का साथ दे। असल में पिछले दिनों एक अध्यादेश लाकर केंद्र ने दिल्ली सरकार के कई अधिकार छीन लिए थे।

इस बीच भाजपा में इस बैठक के मद्देनज़र एक अजीब तरह की खलबली देखी गई। पटना में इस मीटिंग के मद्देनज़र भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ तरह- तरह के पोस्टर लगाए। किसी पोस्टर में विपक्षी नेताओं को ठूस ऑफ़ हिंदुस्तान बताया गया तो किसी पोस्टर में लिखा गया हल्ला है हर ओर, बिहार में मिलेंगे सारे चोर वहीं एक और पोस्टर में लिखा गया लोकतंत्र के हत्यारे आज किस मुँह से जेपी की धरती पर आ रहे हैं? क्या देश में एक बार फिर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? उधर गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी एकता पर तंज कसा- विपक्ष कभी एक होने वाला नहीं है। पटना में तो विपक्षी नेताओं का फ़ोटो सेशन चल रहा है। इससे ज्यादा या अलग कुछ नहीं।

जवाब में ममता बनर्जी ने पटना बैठक में शामिल होने के बाद कहा- दिल्ली में हमने जितनी बैठकें की, विफल साबित हुईं, लेकिन पटना बैठक काफ़ी सकारात्मक रही। नीतीश कुमार के प्रयास आखिर रंग लाए। हम हर हाल में अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कोई मतभेद या कोई बाहरी शक्ति हमें अपने लक्ष्यों डिगा नहीं पाएगी। इस मीटिंग में नीतीश कुमार को विपक्षी एकता या आगे चलकर इस गठबंधन का जो भी नाम तय होगा, उसका संयोजक बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। इस चर्चा का नतीजा क्या रहा, यह तो अभी घोषित नहीं किया गया लेकिन शायद अगली मीटिंग में नाम की घोषणा कर दी जाएगी।

असल में विपक्षी दलों में बिखराव भी भारतीय जनता पार्टी की अपार सफलता का एक बड़ा कारण रहा है। भाजपा एक विचारधारा के साथ चलती है, जबकि बाकी पार्टियों में से केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी मानी जाती है, जिसकी कोई अपनी विचारधारा रही है। और कांग्रेस भी कई बार अपनी विचारधारा से डिगति दिखती रही है। भाजपा के सत्ता पर काबिज रहने का एक ठोस कारण यह भी है कि वह कैडर आधारित पार्टी है और उसके पास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे अराजनीतिक संगठन का राजनीतिक आधार भी है। संघ उसका मातृ संगठन माना जाता है।

परंतु देखा जा रहा है कि सत्ता में काबिज होने के बाद लगभग हर पार्टी की विचारधारा बदलने लगती है। सत्ता पाना और सत्ता पर काबिज रहना ही उसका एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए वह किसी भी विचारधारा से हाथ मिला लेती है। यही नहीं, उसके अंदर भी व्यवहार रूप में शून्यता की ओर चले जाते हैं। सत्ता के लिए कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं, बस ऐसी नीति, जिससे राज और ताज मिल जाए, यह एक सिद्धांत रह जाता है। यही कारण है कि सत्ता में लंबे समय तक रहने वाली कांग्रेस निचले पायदान पर चली गई। अब उसमें कुछ उड़वाण की उम्मीद देखी जा रही है।

तमाम विपक्षी दल ये मानते हैं कि सत्ता में काबिज भाजपा लोकतंत्र और विपक्ष को कुचलने में जुट गई है। केवल विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे, विपक्षी एकजुटता का बड़ा तात्कालिक कारण है। और दिल्ली में चुनौी सरकार के अधिकारों का छीना जाना भी एक वजह है। कुल मिलाकर पटना में हुई बैठक राजनीतिक विशेषज्ञों की राय में सकारात्मक रही है और आने वाले चुनाव में कम से कम पिछले चुनाव जितना बिखराव तो विपक्ष में नहीं दिखाई देगा। और मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस भी धीरे- धीरे मुकाबले में आती जा रही है। कांग्रेस ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए सेक्युरर से साफ़ हिंदुत्व की ओर प्रयाण प्रारंभ कर दिया है। देखना होगा कि कांग्रेस के लिए नया प्रयोग किनना सफल होता है। और विपक्षी एकता का जो राग पटना से निकला है, सफलताओं के आगम तय करेगा या राजनीति की भूलभुलैयाँ में फिर गुम हो जाएगा, इसकी प्रतीक्षा भी रहेगी।

लोकसभा की 200 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन बिगाड़ सकता है बीजेपी का गणित

विपक्षी एकता के लिए पटना में हुई महाबैठक में जुटे 15 विरोधी दलों के नेताओं ने लोकसभा चुनाव- 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में 282 सीटों पर पड़ सकता है। 112 राज्यों की इन 282 सीटों में से अभी 1117 विपक्षी पार्टियों और 165 बीजेपी के पास हैं। पटना की महाबैठक में जुटे 15 दलों के पास अभी लोकसभा की करीब 150 सीटें हैं। वहीं विपक्ष की इस बैठक से दूरी बनाने वाले बीजू जनता दल, वायएसआर कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणीअकाली दल और तेलगू देशम पार्टी जैसे दूसरे सियासी दलों के खाते में लोकसभा की 59 सीटें हैं। आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव- 2024 में मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने की कवायद में जुटे 15 राज्यों के क्षत्रप किस तरह बीजेपी को खेल बिगाड़ सकते हैं।

12 राज्यों की इन 282 सीटों पर पड़सकता है असर : यदि पटना की बैठक के ऐलान के मुताबिक यदि विपक्षी दलों के नेता बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा असर 12 राज्यों की 282 लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। इन 282 सीटों में अभी 117 पटना की बैठक में शामिल हुई विपक्षी पार्टियों और 165 बीजेपी के पास है। बाकी सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं, जो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हुई विपक्ष की महाबैठक में शामिल 15 पार्टियों के पास अभी अपने-अपने राज्यों में लोकसभा की करीब 150 सीटें (कांग्रेस की कुल 52 सीटों सहित) हैं। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस की 52 सीटों के अलावा, बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पास 16, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की 23, तमिलनाडु में डीएमके की 24, महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की 6, एनसीपी की 4, झारखंड में झामुमो के पास 1, जम्मू कश्मीर में ह्छ के पास 3, पंजाब में आम आदमी पार्टी की 2, सीपीआई की 2 और सीपीआईएम की 3 सीट शामिल हैं।

किस तरह भाजपा का गणित बिगाड़ सकते हैं क्षेत्रीय दल: लोकसभा चुनाव 2019 में 169 सीटें ऐसी थी, जहां बीजेपी का क्षेत्रीय दलों से सीधा मुकाबला हुआ था। इनमें मुख्य रूप से यूपी की 74 सीट, बंगाल की 39 सीट, ओडिशा की 19 सीट, महाराष्ट्र की 10 सीट, बिहार की 15 सीट और झारखंड, कर्नाटक की 6-6 सीट शामिल थीं। इन 169 सीटों में 128 सीटों पर चुनाव में कांग्रेस बहुत कम सीटों पर सीधे मुकाबले की स्थिति में थी। खासकर यूपी में लोकसभा की 74, पश्चिम बंगाल में 39, ओडिशा में 19 सीटें पर वो सीधे मुकाबले में थी ही नहीं। यानी इन तीन राज्यों में कांग्रेस का असर न के बराबर था। माना जा रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव- 2024 में विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ते हैं तो इन सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी, सपा, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके और जेएमएम जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच हो जाएगा।

पिछले चुनाव में 97 सीटों पर क्षेत्रीय दलों में रहा मुकाबला : लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के मुताबिक देशभर में 97 लोकसभा की सीटें ऐसी थीं जहां क्षेत्रीय दल ही एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले में थे। मतलब किसी राष्ट्रीय पार्टी के बजाय क्षेत्रीय दल ही पहले या दूसरे नंबर पर रहे। लोकसभा की इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ीं तो तीसरे या चौथे नंबर पर रहीं। इन 97 सीटों में से मुख्यरूप से तमिलनाडु की 27, महाराष्ट्र की 16, बिहार की 16 और



महाबैठक से दूर ये क्षत्रप पलॉप कर सकते हैं गेम प्लान

आंध्र प्रदेश की 25 सीटें शामिल थीं। बाकी की 13 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में गईं। अब यदि विपक्षी एकजुटता के हिसाब से इन 97 में से महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 43 सीटों की बात की जाए, जहां पहले ही विपक्ष का गठबंधन है तो 2024 में बाकी की 54 सीटों पर बीजेपी को विपक्ष से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा।

79 सीटों पर क्षेत्रीय दल वर्सेज कांग्रेस का मुकाबला हुआ था: पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 79 सीटें ऐसी रहीं जहां मुकाबला कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच हुआ। इसमें मुख्य रूप से पंजाब की 10 सीटों पर कांग्रेस और अकाली, तेलंगाना की 11 पर कांग्रेस और बीआरएस, केरल में 15 सीटों पर कांग्रेस-सीपीएम, बिहार में ऐसी 7 सीटें रहीं जहां कांग्रेस का जेडीयू या अन्य क्षेत्रीय दल के बीच मुकाबला हुआ। इसके अलावा अन्य दूसरे राज्यों की 36 सीटों पर भी इसी तरह का चुनावी मुकाबला हुआ। अब यदि 2024 के लिहाज से देखा जाए तो इनमें 36 सीटें ऐसी हैं जहां फिलहाल विपक्ष की एकजुटता संभव नजर नहीं आ रही है। ऐसे राज्यों में केरल और तेलंगाना भी शामिल है जहां कांग्रेस का चुनावी गठबंधन नहीं है।

190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में हुआ सीधा मुकाबला: लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ था। इनमें 175 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 15 सीट जीत पाई थी। इनमें मुख्य रूप से एमपी की 29, गुजरात की 26, महाराष्ट्र की 15, राजस्थान की 24, कर्नाटक की 2, हरियाणा की 9, छत्तीसगढ़ की 11, असम की 9, पंजाब की 3, उत्तराखंड और हिमाचल की 9 सीटें और दिल्ली की 7 सीट शामिल हैं।

विपक्ष की महाबैठक से दूर बीजेडी, बीआरएस, जेडीएस और एसएडी की सियासी ताकत कितनी? अब यदि हम विपक्ष की उन पार्टियों के क्षत्रपों की ताकत पर नजर डालें, जो पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक से दूर रहे और जिनका अभी बीजेपी से भी कोई गठबंधन नहीं है तो ऐसी पार्टियों में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजेडी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बीआरएस (पूर्व में टीआरएस), आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस और कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी की जेडीएस प्रमुख और पंजाब में सुखबीरसिंह बादल की एसएडी प्रमुख है। आपको बताते हैं कि लोकसभा सीटों के लिहाज से इनकी क्या ताकत है और ये अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के 15 दलों की मोर्चाबंदी के मंस्बों के कितना प्रभावित कर सकते हैं।

बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा।

आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की झुस्क कांग्रेस ताकतवर: अब आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां जगन मोहन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटें जीती थीं। यानी मौजूदा समय में प्रदेश में उनकी मजबूत पकड़ है। लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं यानी विपक्षी दलों के साथ न आने पर इस राज्य में भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के लक्ष्य को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्य में जगन मोहन रेड्डी की ताकत के कारण ही बीजेपी उन पर नजर गढ़ाए हुए है। हालांकि, जगन ने भी अभी तक बीजेपी से नजदीकी बनाए रखने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। वे अभी भले ही एनडीए में शामिल न हों, लेकिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन करते रहे हैं। ये ऐसे कई विपक्षी मुद्दों पर भी किनारा करते रहे हैं, जिनके साथ कांग्रेस खुड़ी नजर आती है।

कर्नाटक में सिमटती जेडीएस बीजेपी के करीब : कर्नाटक में हाल के विधानसभा चुनाव से पहले तक जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती रही है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में उसकी सीटें कम हो गई। उसे सिर्फ 19 सीटें मिलीं जबकि 2018 में उसे 37 सीटें मिली थीं। इससे पहले 2013 में उसकी 40, 2008 में 28 और 2004 में 58 सीटें थीं यानी वो राज्य में लगातार अपना जनाधार खो रही है। वहीं लोकसभा में अभी जेडीएस का सिर्फ एक ही सांसद है। राज्य में उसके कांग्रेस से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चर्चा है कि जेडीएस लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संपर्क में है। वे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से चार सीटें मांग रही है। विगत 6 जून को बेंगलुरु में जेडीएस के सुप्रिमो एचडी देवगौड़ा ने बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिशों पर कहा था कि क्या देश में एक भी पार्टी ऐसी है, जिसका बीजेपी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है? उनके इस बयान को बीजेपी से निकटता की संभावना का संकेत माना गया था। यही वजह है कि वो या उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी विपक्षी एकता के लिए पटना बैठक में शामिल नहीं हुए।

विपक्ष के नेता चाहे जितना हाथ मिला लें, दिल नहीं मिलने वाले: अमित शाह

अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के विपक्षी नेताओं के दावों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग कितने भी हाथ मिला लें, लेकिन इनके दिल नहीं मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये कभी साथ नहीं आ सकते हैं। 2024 में भी बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। लोकसभा चुनाव- 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी बैठक पर तंज करते हुए कहा- क्या से क्या हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैं नीतीश कुमार को राहुल गांधी का स्वागत करते हुए देखता हूँ तो लगता है राजनीति में क्या से क्या हो गया। लालू यादव को 22 महीने और नीतीश कुमार को 20 महीने के लिए राहुल गांधी की दादी ने जेल में बंद कर दिया था। दोनों नेता महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन आज ये सभी गलबहियां कर रहे हैं।

ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। लेकिन ये चाहे कितनी गलबहियां कर लें कुछ नहीं होने वाला। अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार फिर बड़े बहुमत से केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाएगी। **द सूत्र।**

झूट बोले कौआ काटे ! यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाय री वोट की राजनीति...

रामेन्द्र नाइक

समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। प्रश्न तो यह है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल इस मुद्दे के साथ वोट बैंक की राजनीति किसने की, जबकि शाहबानो प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि ‘संसद को एक सामान्य नागरिक संहिता की रूपरेखा को रेखांकित करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष राष्ट्रीय सद्भाव और समानता की सुविधा देता है।’

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि वे शीघ्र ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। यह भाजपा का पायलट प्रोजेक्ट होगा। उधर, भारत के विधि आयोग ने 14 जून, 2023 को समान नागरिक संहिता पर राय और टिप्पणियां मांगने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। यह 21वें विधि आयोग द्वारा अगस्त 2018 में इसी मुद्दे पर एक परामर्श पत्र जारी करने के बाद पांच साल के अंतराल पर आया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तो पिछले साल ही मंशा जता दी थी कि अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के बाद अब समान नागरिक संहिता की बारी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो 9 वर्ष पहले ही बतौर भाजपा सांसद समान नागरिक संहिता का मुद्दा संसद में उठाते हुए इसे देश की एकता-अखंडता के लिए जरूरी बताया था।

पिछले साल, गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने विचार-विमर्श तथा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समितियों का गठन तक कर दिया। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी कानून लागू करने की तैयारी है। मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 में समान नागरिक संहिता के लिए समिति बनाने का ऐलान किया तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन प्रदेशों में नागरिक समान संहिता लागू करने की योजना पर काम हो रहा है, उनसे हम सुझाव ले रहे हैं।

कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दल सीएम धामी की ताजातरीन घोषणा और विधि आयोग की पहल से बौखला

गए हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटका रही है और ध्ववीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप से जायज ठहराने के लिए व्याकुल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद में बहस कराने की मांग की। वहीं, समान नागरिक संहिता पर धार्मिक निकायों से भी राय मांगे जाने को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने आरोप लगाया कि देश की सरकार ‘राजनीति में धर्म गुरुओं को ला रही हैं’। धर्म गुरुओं को मत चलाना चाहिए पूजा करनी चाहिए। वे (केंद्र सरकार) उनका प्रवेश करारक हंगामा कर रहे हैं।

भाजपा ने कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर आरोप लगाया कि वह कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई है और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कदम का विरोध कर रही है। यह कुछ ऐसा है जिसे कांग्रेस को अपनाना चाहिए था क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू (पहले प्रधानमंत्री) और संस्थापक (संविधान के) थे, जिनमें से कई कांग्रेस से थे और जिन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत की थी।

दूसरी ओर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सरकार का फैसला नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। यह कानून देशहित में नहीं है। भाजपा इसे चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है।

झूठ बोले कौआ काटे: समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। अध्याय के अनुच्छेद 44 में कहा गया है, ‘राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।’

1985 में शाहबानो तलाक मामले में एक मुस्लिम महिला के अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘संसद को एक सामान्य नागरिक संहिता की रूपरेखा को रेखांकित करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष राष्ट्रीय सद्भाव और समानता की सुविधा देता है।’

शाहबानो मामला ही नहीं, नागरिकता (संशोधन) कानून (सीए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी),

जुममे पर स्कूलों में छुट्टी और हिजाब पर बवाल हो या दूसरी शायी के लिए मुस्लिम बनने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र चंद्रमोहन और हरियाणा की पूर्व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनुराधा बाली उर्फ फिजा के निकाह जैसे किस्से, समान नागरिक संहिता हमेशा बहस का मुद्दा बनता रहा है।

2015 में एबीसी बनाम दिल्ली राज्य मामले में, सर्वोच्च



न्यायालय ने कहा कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चों के ‘प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं’ दी जाती है, भले ही हिंदू अविवाहित महिलाएं अपने बच्चे की ‘प्राकृतिक अभिभावक’ हों। तब भी, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि समान नागरिक संहिता ‘एक अनुसूलीय संवैधानिक अपेक्षा बनी हुई है’। देश की शीर्ष अदालत की ओर से कई बार कहा गया कि देश में अलग-अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति बन जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में निराशा जताई थी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई ठोस कोशिश नहीं की गई है।

जबकि, समान नागरिक संहिता के विरोध में तर्क देने वालों का कहना है कि संविधान के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हर व्यक्ति को धार्मिक

स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए, हर धर्म के लोगों पर एक समान पर्सनल लॉ थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। मुस्लिम इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं।

बोले तो, संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के समर्थन में थे। आजाद भारत में महिलाओं की

स्वतंत्रता और समानता के लिए अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता को बेहद जरूरी बताया था। लेकिन, वोट बैंक की राजनीति इसमें एक बड़ी बाधा बनी।

मुस्लिम नेताओं के भारी विरोध के कारण देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू समान नागरिक संहिता पर आगे नहीं बढ़े। जबकि, 1954-55 में भारी विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून 1956 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता कानून 1956 लागू हुए। इससे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे नियम संसद में बने कानून से तय होने लगे। लेकिन, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को अपने-अपने धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दे को तय करने की छूट बरकरार रही।

अभी, भारत में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून बड़े पैमाने पर उनके धर्म द्वारा शासित होते हैं। जबकि, दुनिया के लगभग सभी देशों में उनके सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता होने से देश की अदालतों पर लगातार बढ़ते मुकदमों के बोझ को हल्का करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि इन धार्मिक

कानूनों की वजह से चल रहे दिवानी यानी सिविल मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी हिंदू कानून वेद पुराण, स्मृति आदि के आधार पर तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान, सुन्नत, इज्मा, कयास और हदीस के आधार पर हैं। इसी तरह ईसाइयों का कानून बाइबिल, पुराने अनुभव, तर्क और रूढ़ियों के आधार पर जबकि पारसियों का कानून उनके पवित्र धार्मिक ग्रंथ जेंद अवेस्ता पर आधारित है।

भाजपा ने समान नागरिक संहिता को पिछले चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया। नवंबर 2019 और मार्च 2020 में इस पर विचार के लिए संसद में दो बार निजी विधेयक पेश किए गए, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के कारण इन्हें वापस ले लिया गया। एक बार फिर, एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने का वक्त आ गया है। वरना, कब तक देश वोटबैंक की राजनीति का शिकार होता रहेगा!

और ये भी गजब:

पैंतीस मुस्लिम-बहुल और 18 मुस्लिम-अल्पसंख्यक देश औपचारिक रूप से मुस्लिम पर्सनल कानूनों को अपनी कानूनी व्यवस्था में एकीकृत करते हैं और उन्हें राज्य अदालतों के माध्यम से लागू करते हैं। मुस्लिम-बहुल और मुस्लिम-अल्पसंख्यक दोनों सरकारों ने मौलिक मानवाधिकारों पर धार्मिक कानूनों के प्रभाव को कम करने, जवाबदेही और पहुंच बढ़ाने और अपने मुस्लिम पर्सनल कानून सिस्टम के भीतर कानून के शासन को मजबूत करने के लिए विधायी सुधार किए हैं। भारत को छोड़कर दूसरे देशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ में काफी सुधार हुए हैं। मुस्लिम बहुल देशों की बात करें तो बहुविवाह और तीन तलाक जैसी लैंगिक असमानता वाली प्रथाओं को भी समाप्त कर दिया गया है। द्यूनीशिया, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इराक, सोमालिया, सीरिया, मिस्त्र, मोरक्को, ईरान जैसे देशों में एक से अधिक पति-पत्नी होने के कृत्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जबकि, भारत में 1930 के दौर में बना मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी तक लोगों पर थोपा जा रहा है।

मप्र में पुलिस आरक्षक के 7090 पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी



भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पुलिस विभाग में करिअर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। आवेदन की प्रक्रिया 26 जून 2023 से शुरू होगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 तक है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट द्रष्टा.इंश1.द्रुटु पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों के पास 15 जुलाई तक समय है।

एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2023 की यह अधिसूचना कुल 7,090 स्थितियों को भरने के जारी की गई है। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों को 10 जुलाई 2023 तक रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। विभाग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 12 अगस्त 2023 को आयोजित की जाएगी।

दो पालियों में परीक्षा- भर्ती परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा समय के अनुसार, उम्मीदवारों को सुबह की पाली के लिए 7.30 से 8.30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और परीक्षा सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती, निर्धारित प्रपत्र में भेजें जानकारी, विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी



भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य शासन के विभिन्न विभाग में चल रही एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पोर्टल पर देने के लिये विभाग प्रमुखों को कहा है। साथ ही जानकारी संबंधी प्रपत्रों को समय-समय पर अद्यतन करने के भी निर्देश दिये गये हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को अपने विभाग से संबंधित प्रपत्रों को 27 जून 2023 तक अनिवार्यतः अद्यतन करने के लिये कहा गया है।

गैलेक्सी एफ 54 5जी की सेल से शुरू हुइ

गुरुग्राम, एजेंसी। सैमसंग के सबसे प्रीमियम एफ सीरीज़ स्मार्टफोन, गैलेक्सी एफ 54 5जी की सेल से शुरू हुइ। गैलेक्सी एफ 54 5जी की स्लीक और प्रीमियम एस्थेटिक्स के साथ गैलेक्सी के आईकोनिक सिग्नेचर डिजाईन के कारण यह स्मार्टफोन बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। गैलेक्सी एफ 54 5जी में श्रेणी की अग्रणी विशेषताएं हैं, जैसे इसमें 108मेगापिक्सल का नो शेक कैमरा, फ्लैगशिप कैमरा फीचर्स, जैसे एस्ट्रोलेप्स और नाईटोग्राफी, 6000 एमएएच की शक्तिशाली बैटरी और एक बेहतर सुपर एमोलेड+ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, जिसके कारण यह ग्राहकों को बहुत ही पसंद आएगा।इस स्मार्टफोन में अन्य आकर्षक विशेषताएं जैसे वॉइस फोकस और सैमसंग वॉलेंट मशहूर नॉक्स सिक्योरिटी द्वारा सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। यह लेटेस्ट वन यूआई 5.1 पर चलता है। इसके साथ चार जनरेशन तक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट और पाँच साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, ताकि यूजर्स का अनुभव सदैव विश्वसनीय व अप-टू-डेट बना रहे।

ग्रासिम को मिला इकोनॉमिक टाइम्स सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 का ख़िताब

नई दिल्ली , एजेंसी। भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह का एक हिस्सा द इकोनॉमिक टाइम्स सस्टेनेबिलिटी सहित देश के अधिकतम आर्थिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं पर इंडिया इंक के लिए पैदा हो रही चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 उन कंपनियों को पहचानने और सम्मानित करने का एक प्रयास है जिन्होंने बाजार में उत्कृष्ट सेवाओं का प्रदर्शन किया है। इसका उद्देश्य है कि कंपनियों द्वारा सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कर रहे योगदान के लिए उन्हें सराहना दी जाए और उनके काम और परिश्रम को सम्मानित किया जाए। कंपनियों को इनोवेशन, ईएसजी गोल, रिस्पोसिबल बिसनेस एक्टिविटी और अन्य पैरामीटरों पर मूल्यांकन करने के बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यह इटी सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 का ख़िताब दिया गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को सीएफओ, पवन जैन ने कहा, यह गौर की बात है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने ग्रासिम को सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 के रूप में यह ख़िताब दिया है।

नेस्ले ने भारत में अपने ब्रेकफास्ट सीरियल्स पोर्टफोलियो काविस्तार किया

नई दिल्ली , एजेंसी। अपने नाश्ते के मेन्यू में थोड़ी और वैरायटी शामिल करने के लिए, नेस्ले ब्रेकफास्टसीरियल्स ने भारत में अपने पोर्टफोलियो में दो नए प्रोडक्ट्स, कोको क्रंच मिलेट-ज्वारऔर मंच ब्रेकफास्ट सीरियल की पेशकश की है। नेस्ले इंडिया के लिए इनोवेशन औरप्रोडक्ट में नयापन लाना सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ब्रेकफास्ट सीरियल के अलग-अलग तरह के विकल्पों की पेशकश करती है।कोको क्रंच मिलेट-ज्वार ब्रेकफास्ट सीरियल्स नयापन लाने की दिशा में बढ़ावा गया एककदम है, जहां अनाजों के राजा (किंग ऑफ मिलेट्स) के रूप में मशहूर ज्वार जैसेस्थानीय अनाज को इसमें पहले से ही मौजूद चावल और गहूँ जैसे अनाजों के साथमिलाया गया है। अपने बेहतरीन चॉकलेटी स्वाद के साथ, कोको क्रंच फैमिली की सुबहमजेदार बनाने में मदद कर रहा है। मंच ब्रेकफास्ट सीरियल्स उन लोगों को खुशी देने के लिए तैयार किया गया है जोकिमीर्क के अनुसार और ज्यादा स्वादिष्ट नाश्ते के विकल्प तलाशते रहते हैं।

बिजली होगी 20 प्रतिशत सस्ती! टैरिफ में संशोधन, केंद्र सरकार ने लागू किया नया नियम

नई दिल्ली। बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है. हर महीने ज्यादा बिजली का बिल भर-भर के परेशान हो गए हैं तो अब थोड़ी सी प्रबंधन कर आप अपने बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से बिजली बिल को कम करने के लिए टैरिफ में संशोधन कर नया नियम लागू किया जा रहा है, जिससे आपका बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा. सरकार बिजली की दरें तय करने के लिए ‘दिन के समय’ का नियम लागू करने वाली है. ऐसा होने पर देशभर के बिजली उपभोक्ता सौर घंटों (दिन के समय) के दौरान बिजली खपत का प्रबंधन कर अपने बिजली बिल में 20 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे।

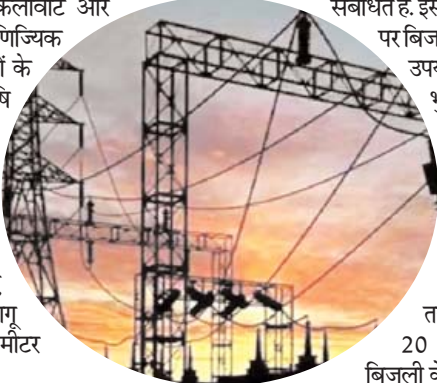
बता दें नए नियम टीओडी के तहत दिन के अलग-अलग समय के लिए बिजली की अलग-अलग दरें लागू होंगी. यह व्यवस्था लागू होने से बिजली की सर्वाधिक दर वाले समय (पीक ऑवर्स) में ग्राहक कपड़े धोने और खाना पकाने जैसी अधिक बिजली खपत वाले कामों से परहेज कर सकेंगे।

इस तरह कम कर सकेंगे बिजली का बिल- उपभोक्ता नई व्यवस्था के तहत कपड़े धोने या खाना पकाने

जैसे कार्य सामान्य कामकाजी घंटों में करते हुए अपना बिजली बिल कम कर सकेंगे. ज़थष्ट शुल्क व्यवस्था एक अप्रैल, 2024 से 10 किलोवाट और उससे ज्यादा मांग वाले वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू हो जाएगी. कृषि छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू होगा. हालांकि, स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टीओडी व्यवस्था तभी लागू होगी जब वे इस तरह का मीटर लगवाएंगे.

समय के हिसाब से अलग-अलग होगी बिजली की कीमत- बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि भारत सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन कर मौजूदा बिजली शुल्क प्रणाली में दो बदलाव किए हैं. ये

बदलाव दिन के समय शुल्क प्रणाली की शुरुआत और स्मार्ट मीटर से जुड़े प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित हैं. इसके मुताबिक, दिन भर एक ही दर पर बिजली के लिए शुल्क लेने के बजाय उपयोगकर्ता द्वारा बिजली के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत दिन के अलग-अलग समय के हिसाब से अलग-अलग होगी. बयान के मुताबिक, नई शुल्क प्रणाली के अंतर्गत सौर घंटों में बिजली की दर (राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा आठ घंटे तय की गई) सामान्य दर से 10 से 20 प्रतिशत कम होगी, जबकि बिजली के सर्वाधिक उपयोग के समय से यह 10 से 20 प्रतिशत ज्यादा होगी। **केंद्रीय मंत्री ने कहा सभी को होगा फायदा-** केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि टाइम ऑफ डे टैरिफ सिस्टम देश के पावर सिस्टम के साथ उपभोक्ताओं के हक में है.



बहुत काम की है टोल नाके की रसीद, संभाली तो 5 सुविधाएं फ्री

नई दिल्ली। जब हाइवे से कहीं जाएं तो रास्ते में पड़ने वाले टोल नाके पर टैक्स तो सभी देते हैं। लेकिन, कोई भी मिलने वाली रसीद को नहीं देखता। सामान्यतः लोग उसे फेंक देते हैं। लेकिन, ये रसीद बहुत काम की है और किसी की जिंदगी भी बचा सकती है। हाईवे पर कोई मुसीबत आने पर यह रसीद कई तरीके से मदद कर सकती है। इन रसीदों के कई फायदे हैं, इसलिए जब तक यात्रा जारी है, तब तक इसे संभालकर रखें।

नेशनल हाईवे के टोल बूथ पर पैसे देने के बाद आपको जो रसीद मिलती है, उस पर आपको एक से चार फोन नंबर आगे-पीछे के हिस्से पर जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये फोन नंबर हेल्पलाइन, फ़ोन सर्विस, एंजुलेंस सर्विस और पेट्रोल सर्विस के दिए जाते हैं। बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यात्रा के दौरान टोल शुूल लेन में आपको ये सभी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये चारों नंबर आपको नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की साइट पर भी आसानी से मिल जाएंगे।

फ़ोन में मिलती है ये सुविधाएं- नेशनल हाईवे के टोल बूथ पर पैसे देने के बाद जो रसीद मिलती है, उस पर एक से चार फोन नंबर आगे-पीछे के हिस्से पर जरूर मिल जाएंगे। ये फोन नंबर हेल्पलाइन, फ़ोन सर्विस, एंजुलेंस सर्विस और पेट्रोल सर्विस के दिए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यात्रा के दौरान टोल शुल्क लेन ये सभी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

तुरंत मिलती है मदद - इन सभी हेल्पलाइन नंबर पर आप-गुप्त भी फोन करेंगे, तब फोन उठायी जाएगा। अगर रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 1033 या 108 पर फोन कर सकते



हैं, इस दौरान तुरंत मदद मिलेगी। ये सेवा लगातार 24 घंटे चलती है।

मेडिकल इमरजेंसी का नंबर- नेशनल हाईवे पर यात्रा के समय कभी-कभी मेडिकल इमरजेंसी की भी स्थिति बनती है। आप बीमार भी हो सकते हैं। ऐसे में रसीद के आगे या दूसरी तरफ दिए मेडिकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल के 10 मिनट बाद ही एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एंजुलेंस उपलब्ध कराने वाली हेल्पलाइन का नंबर 8577051000 और 7237999911 है। ये सुविधा बिलकुल फ्री है। इसपर कॉल करके एम्बुलेंस तुरंत यहाँ तक पहुंच जाएगी।

पेट्रोल हेल्पलाइन नंबर- अचानक से किसी वजह से गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सड़क के किनारे वाहन खड़ा करके, रसीद पर दिए हेल्प लाइन नंबर या फिर

पेट्रोल नंबर पर फोन कर सकते हैं। आपको 5 या 10 लीटर लीटर के पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति कर दी जाएगी। लेकिन इस ईंधन की रकम का भुगतान आपको करना पड़ेगा। पेट्रोल हेल्पलाइन नंबर 8577051000, 7237999944 है।

हेल्पलाइन पर कॉल करने से पहले जरूरी बातें?— टोल की रसीद आपके द्वारा ही खरीदी होनी चाहिए, किसी पुरानी रसीद के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल न करें। पेट्रोल खत्म होने पर टोल कंपनी पेट्रोल सप्लाई नहीं करती और न ही फ्री पेट्रोल या डीजल देती है। टोल कंपनी इमरजेंसी के समय आपको सारी सुविधाएं फ्री में देगी। टोल कंपनी गाड़ी खराब होने पर दिया गया पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के लिए दिया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंकर हो जाता है, तो आप रसीद पर लिखे नंबर पर कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं। आपकी मदद 10 मिनट में पूरी की जाएगी।

गोदरेज एग्रोवेट मना रहा है अपने बायोस्टिमुलेंट ‘डबल’ की 25वीं वर्षगाँठ

होशंगाबाद। गोदरज एग्रोवेट लिमिटेड (जीएवीएल) के क्रॉपप्रोटेक्शनबिजनेस ने आज घोषणा की कि इसके बायोस्टिमुलेंट, ‘डबल’ ने भारतीय किसानों के लिए बेहतर उपज को सक्षम करने के 25 साल पूरे कर लिए हैं। डबल ने लगभग 3 करोड़ एकड़ भारतीय कृषि भूमि का उपचार किया है और पिछले 25 वर्षों में लगभग 2 करोड़ कृषक परिवारों के जीवन में समृद्धि लाई है। कंपनी ने डबल के 25 साल पूरे होने और किसानों को नकली उत्पादों से बचाने के अलावा बेहतर खेती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए एक विशेषपैक की लॉन्च किया। डबल का नया पैक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और यह सुरक्षित पैकेजिंग बोतल में आता है। इसमें एक टैम्पर-रूविडेंट सील है जो बोतल को खोलने की कोशिश करने पर फट जाती है और गिर जाती है। नकलीपन से

बचने के लिए लेबल में जटिल वॉटरमार्क हैं। और बोतल परहोलोग्राम भी है ड्रूजो विशिष्ट 9-अंक के कोड के रूप में है। यह प्रत्येक बोतल पर मौजूद है ताकि प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।जर्होहोलोग्राम में ग्राहक को आश्चस्त करने के लिए स्मार्ट तरीके से त अक्षर भी डाला गया है कि उत्पाद वास्तविक है, वहीं नेत्रहीनों के लिए बोतल की नेक पर ब्रेल लिपि में डेंजरअंकित किया गया है। डबलएक बायोस्टिमुलेंट है जो फिकपास, सोयाबीन, मूंगफली और सब्जी (टमाटर) की फसलों में फूलों और फलों का झड़ना कम करता है। फूलों और फलों के गिरने के चलते किसानों की 15प्रतिशत-25प्रतिशत तक उपज प्रभावित होती है। उचित तरीके से खेती करके और सही मात्रा में डबल का प्रयोग करने से, किसानों को उनकी उपज बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

आश्रय गुपु ने पेश किया गोल्डन गैर्डे: बिज़नेस एवं रिटेल रीयल एस्टेट को नए सिरे से परिभाषित करती 1284 करोड़ रुपये के निवेश से एक लैंडमार्क परियोजना

नई दिल्ली, एजेंसी। नयी पीढ़ी की रीयल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी आश्रय इन्फ़्र ने ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में अपनी अग्रणी अद्भुत परियोजना गोल्डन ग़्रैंड की आज घोषणा की। पच्चीस एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह परियोजना एक आईटी और इससे जुड़ी है और दिल्ली एनसीआर में सभी कामकाजी लोगों के लिए खरीदारी एवं खाने पीने का वन स्टॉप आइकॉनिक हाई स्ट्रीट रिटेल एवं बिज़नेस हब है। पांच किलोमीटर की परिधि वाले इस क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की अनुमानित आबादी है जहां गोल्डन ग़्रैंडे सबसे बड़े टेक जोन्स में से एक में स्थित है और यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और जेवर हवाईअड्डा के काफी करीब है और यह दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे, एमएनजी एक्सप्रेसवे, डीएनडी फ्लाईवे और किसान चौक मेट्रो स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

आश्रय इन्फ़्र गोल्डन ग़्रैंड के विकास में 1284 करोड़रुपये का निवेश कर रही है। गोल्डन ग़्रैंडे के प्रथम चरण में 631 करोड़ रूपये का शुरुआती निवेश किया जाएगा जिससे इस परियोजना को लेकर



कंपनी की प्रतिबद्धता झलकती है। इस परियोजना से पहले, इन भागीदारों ने ग्रेटर नोएडा पश्चिम में श्गोल्डन आईशं नाम से 25 एकड़ की विशाल आई और आईटी से जुड़ी परियोजना की सफलतापूर्वक डिलीवरी की। उत्कृष्टता और गुणवत्ता को लेकर प्रतिबद्धता का इनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिससे इस उद्योग में एक विश्वसनीय डेवलपर के तौर पर इसने प्रतिष्ठा हासिल की है। यह कंपनी उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जिन्होंने

कोरोना काल के दौरान भी अपनी परियोजना गोल्डन आई का निर्माण जारी रखा। इससे कंपनी रिकॉर्ड ढाई साल में 20 लाख वर्ग फुट निर्माण की समय पर डिलीवरी करने में समर्थ रही और इसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसा बेंचमार्क स्थापित किया जो पहले भी नहीं रहा। गोल्डन ग़्रैंडे परियोजना आठ एकड़ के हेबरे क्षेत्र में फैली है और वैश्विक डिजाइन एवं अवधारणा के आधार पर इसे लीड्स और गृह प्रमाण पत्र हासिल है। 1,000

एकड़ से अधिक क्षेत्र के रिहाइशी विकास के बीच रणनीतिक रूप से स्थित इस परियोजना से निकट भविष्य में आसपास बसने वाले 10 लाख लोगों की जरूरतें पूरी करेंगी। इस आइकॉनिक परियोजना में तीन तरफसे खुली लंगरी रिटेल जगह है और 900 मीटर का सामना है एक एक समकालीन डिजाइन को पेश करता है और एक आलीशान एवं जबरदस्त वातावरण में काम करने, खरीदारी करने और खानपान का लुफ्त उठाने की सुविधा की पेशकश करता है। इस परियोजना की भावी जरूरतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित चार्जिंग स्टेशनों, सोलर एनर्जी बैकअप और जीरो लिफ्टिड वेस्ट डिस्चार्ज सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा के मानक अपनाए जाएंगे।

आश्रय रूप के प्रबंधनिदेशक आनन्द शुक्ला ने इस परियोजना के बारे में उत्साह प्रकट करते हुए कहा, श्गोल्डन ग़्रैंडे आज के युवाओं की गतिशील जरूरतें पूरी करने वाले अवधारणा स्थलों को तैयार करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है।



परिवार की आर्थिक मुश्किलों को समझते हुए, हैमेटो-ऑर्कोलॉजिस्ट एवं बीएमटी विशेषज्ञ, डॉ. शैलेश बांबोडेन एओआई के स्टाफ के साथ मिलकर इलाज के खर्च के लिए फंड जुटाने का एक अभियान शुरू किया, ताकि दीपाली को खर्चसे बेहतरीन उपचार मिल सके। उसकी गंभीर स्थिति

को देखते हुए और उसके परिवार के साथ परामर्श करके, डॉ. शैलेश बांबोडे ने कीमोइम्युनोथैरेपी करने की सलाह दी। कीमोइम्युनोथैरेपी कैंसर के इलाज में एक नई खोज है, जो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने के लिये इम्यून सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करती है और पारंपरिक कीमोथैरेपी से जुड़े साइड इफेक्ट्स को कम करती है। इसमें इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवाओं के साथ कीमोथैरेपी की दवाएं दी जाती हैं और कैंसर की कोशिकाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लक्ष्य बनाकर नष्ट किया जाता है।एओआई नागपुर के बीएमटी विशेषज्ञ, डॉ. शैलेशबांबोडेन कहा, अव्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया -यह ब्लड कैंसर का प्राथमिक और प्रमुख प्रकार है।

भोपाल में आज लेखक नियाज खान की पुस्तक ब्राह्मण द ग्रेट का विमोचन

भोपाल। इंडा पालिशिंग हाउस द्वारा लेखक नियाज खान की पुस्तक ‘ ब्राह्मण द ग्रेट’ का विमोचन किया जाएगा, यह कार्यक्रम शाम 5 बजे हिंदी भवन में होगा। इस कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क रहेगा।आईएएस नियाज खान ने जानकारी दी है कि 10 दिनों में किताब अमेजन और ईबुक अमेजन किंडल पर भी उपलब्ध होगी. उन्हें उम्मीद है कि यह पुस्तक उन ब्राह्मणों के बारे में वर्तमान सोच को बदल देगी

नियाज खान ने ट्वीटर पर लिखा है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण द ग्रेट क्यों लिखा? मैंने कहा कि ब्राह्मण बहादुरी का नाम है, ब्राह्मण दयालुता और ईमानदारी का नाम है, ब्राह्मण एक प्रतिभा का नाम है, ब्राह्मण बलिदान का नाम है. उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मण देशभक्त का नाम है, ब्राह्मण सहनशीलता का नाम है, ब्राह्मण संस्कृति और धर्म का रक्षक है.यह पुस्तक आधुनिक ब्राह्मणों के व्यवहार को भी बदल देगी, जो आधुनिकीकरण और भौतिकवाद से पीड़ित हैं. लेखक ने कहा कि ब्राह्मण बहादुरी का नाम है, ब्राह्मण दयालुता और ईमानदारी का नाम है, ब्राह्मण एक प्रतिभा का नाम है, ब्राह्मण बलिदान का नाम है।



बिजली कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु
उपरांत विभाग ने प्रदान की अनुग्रह राशि



छिंदवाड़ा। विद्युत विभाग के पूर्व संभाग छिंदवाड़ा अंतर्गत वितरण केन्द्र लिंगा में कार्यरत रहे बाह्यय स्त्रोत कर्मचारी उदयभान धुवें पिता कृष्णा धुवें की दिनांक 10/9/2021 को थाना मोहखेड़ अंतर्गत ग्राम बडगोनाजोशी में घटित घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसमें विभाग की ओर से मृतक कर्मचारी के पिता कृष्णा धुवें को कार्यालय कार्यापालन अभियंता पूर्व संभाग की ओर से की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप राशि चार लाख रूपए अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान किए गये। हितग्राही कृष्णा धुवें को अनुग्रह राशि चार लाख रूपए चेक के माध्यम से प्रदान की गई। वितरण केन्द्र लिंगा के कनिष्ठ अभियंता द्वारा हितग्राही को चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभाग के कर्मचारी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलना चाहती है भाजपा: धीरज सूर्यवंशी
 छिन्दवाड़ा। मध्यप्रदेश में विगत 20 वर्षों से भाजपा के एकछत्र राज से उनके नेताओं में घमंड आ चुका है। उन्होंने सत्ता की छांव में शासन का दुरुपयोग कर घपले, घोटाले और गबन किये, इससे जुटाई हुई राशि से अब भाजपा के वे नेता भी चौपटहिया वाहन से घूम रहे हैं, जिन्होंने कभी साइकिल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, किन्तु उनकी चूना लगातक की कला ने उन्हें करोड़पति बना दिया। संतरांचल क्षेत्र में वैध अवैध उत्खनन से करोड़पति बने भाजपा के नेता सत्ता की शक्ति से शक्तिमान बनकर लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार भाजपा सरकार की कमियों को खुलकर उजागर कर रहे हैं। शासन, प्रशासन और सरकार की कमियों को पत्र, पत्रिकाओं व समाचार पत्रों के साथ ही टीवी चैनलों के माध्यम से पत्रकार खुलासा करते हैं ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो सके और आमजन की समस्याओं की ओर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यानकार्षण हो सके।

गरज के साथ बिजली चमकने व भारी बारिश होने संभावना
 छिंदवाड़ा। भोपाल द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 120 घंटे के दौरान (24 जून ३ 28 जून 2023) घने से मध्यम रहने एवं दिनांक 25.06.2023-26.06.2023 को हल्की बारिश होने एवं दिनांक 24.06.2023, 27.06.2023-28.06.2023 को भारी से बहुत भारी बारिश होने एवं गरज के साथ बिजली की संभावना है । अधिकतम तापमान 31-34 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 22-26 डिग्री. सेन्टीग्रेट के मध्य रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 82-88 प्रतिशत एवं न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 49-62 प्रतिशत रहने की संभावना है । आने वाले दिनों में हवा पश्चिम दिशा में बहने एवं 14-19 कि. मी. प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है ।

रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम आज छिन्दवाड़ा। सर्व आदिवासी समाज छिन्दवाड़ा के मौडिया प्रभारी राकेश मरामन ने बताया बीरगंगा रानी दुर्गावती का 459 वाँ बलिदान दिवस का आज दिनांक 24/06/2023 को खजुरी चैक पर रखा गया 12 बजे बीरगंगा महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं बड़ादेव सुमरणी का कार्यक्रम होगा एवं सगजनों सम्मान प्रबुद्धजनों का उद्बोधन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं 5:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा । सर्व आदिवासी समाज से कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु सगजनों से अपील की है।

पं. मनीष बने प्रदेश संगठन मंत्री
 छिंदवाड़ा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश इकाई के मुख्य संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडेय जी एवं प्रदेश प्रभारी पंडित भूपेन्द्र बालोटिया की सहमति पर प्रदेश महासचिव पंडित अमित शर्मा बैतूल की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष पंडित दिशो डंडोटिया जी द्वारा पंडित मनीष तिवारी छिंदवाड़ा 8839050197 को प्रदेश संगठन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

एडीआर भवन जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में रक्तदान शिविर आज

छिंदवाड़ा। प्रधाा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सविता ओगले के मार्गदर्शन में 24 जून 2023 को ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय खोब्रागड़े ने बताया कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है। प्रतिवर्ष देश में समय पर रक्त न मिलने के कारण अनेकों लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। हम रक्तदान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं। रक्तदान करने से किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी भी नहीं आती है । उन्होंने नगर के गणमान्य लोगों से अपील की है कि वे 24 जून 2023 को आयोजित रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें

भीषण गर्मी से मिली राहत



छिंदवाड़ा। शुक्रवार सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ था। सुबह 10 बजे से प्री मानसून ने अपनी दस्तक दी, जिससे गर्मी से राहत मिली और किसानों के चेहरे खिले।

क्षेत्र में धड़हले से चल रहा रेत का अवैध व्यवसाय

दिन हो या रात पूरे समय चलता है खेल,ट्रैक्टर सहित ट्रकों का होता है उपयोग,तगड़ी सेटिंग के चलते नहीं बोलते अधिकारी



छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव इन दिनों इस समूचे क्षेत्र अंबाड़ा मैं रेत का व्यवसाय धड़हले से चल रहा है, हो या रात पूरे 24 घंटे यहां खेल चलता है इस व्यापार में ट्रैक्टर सहित ट्रक दोनों का उपयोग होता है रेत माफिया की इतनी तगड़ी सेटिंग रहती है कि अधिकारी जो भी नहीं बोलते हैं इस अवैध व्यापार से भले ही अधिकारियों का फायदा हो रहा है, नीतू शासन को भारी नुकसान हो रहा है क्षेत्र के जागरूक लोग भोपाल के सीएम से ना सिर्फ लिखित शिकायत करेंगे अपितु रेत भंडारण की फोटो और बने वीडियो सभी तो सौंपेंगे।

सनद रहे कि कोयलांचल की नगरी में प्राय, सभी प्रकार के अवैध धंधे फल फूल रहे हैं, इसी में रेत का अवैध व्यापार है जो क्षेत्र में पिछले कई महीनों से फल फूल रहा है रेत माफिया इस व्यापार के लिए ट्रैक्टर सहित ट्रक का उपयोग करते हैं , क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी इतनी तगड़ी सेटिंग है कि



उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती है ।

चहू और चल रहे हैं निर्माण कार्य

पिछले काफी समय से समूचे क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े-बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो रेत के बिना अधूरे हैं जैसे ही जहां निर्माण कार्य चलने की सुगंध रेत माफिया को आती है वहां पहुंच जाते हैं एवं मोल भाव तय करके ट्रैक्टर ट्रक से रेत गिराने का कार्य शुरू कर देते हैं फिर खेल चलता रहता है।

फ़ी में उठाते हैं रेत नदियों से

अन्य व्यापार की तरह यह व्यापार नहीं है कि पहले रुपया लो फिर बाद में कमाओ इस व्यापार में ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रैक्टर ट्रक की सेटिंग करके इसके हो जाने के बाद फिर अधिकारियों को विश्वास में लेकर व्यापार शुरू हो जाता है। और नदियों से फ़ी की रेत उठा यहां बिक्री करना है रेत की भी और यहां ट्रैक्टर से लाए तो 5000 एवं ट्रक से लाए तो 20 से १25000 तक गए।

कट्टा नदी से आ रही रेत

वर्तमान समय में क्षेत्र में जहां से रेत आ रही है इस नदी में रेत बड़े पैमाने पर है रेत माफिया यहां नजर गड़ा रख कर रखे हुय हैं, एवं सनदी से रेत निकाल समूचे क्षेत्र में बेच रहे हैं।

सीएम से होगी शिकायत

क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर रेत का अवैध व्यापार चल रहा है उसकी लिखित शिकायत प्रदेश के सीएम को होगी, साथी रेत के फोटो एवं वीडियो भी दिखाएंगे क्योंकि क्षेत्र के संबंधित अधिकारी कार्यवाही करेंगे नहीं क्योंकि वह सेट है, जो उनकी मजबूरी बन गई है।

घर में फंदा लगाकर युवती ने किया सुसाइड जेल महानिदेशक ने जिला जेल का किया निरीक्षण

अमरवाड़ा के करबडोल का मामला, सुसाइड नोट भी बरामद
 पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द कर दिया है।
सुसाइड नोट हुआ बरामद, पुलिस नहीं दे रही जानकारी
 गौरतलब हो कि लड़की के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें साफ तौर पर एक युवक का नाम लिखा है तथा उसने सीधे तौर पर लिखी है कि उसके साथ युवक ने गलत किया है। हालांकि इसको लेकर जब अमरवाड़ा के थाना प्रभारी मोहन मर्सकोले से बात की गई तो उन्होंने मामले को जांच में कहकर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी।

एक संदिग्ध किया गया राउंडअप
 बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवती के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर एक युवक को राउंडअप भी किया है लेकिन किसी भी तरह की कोई जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी जा रही है जिससे समझा जा सकता है कि पुलिस इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है मामला जो भी हो लेकिन लड़की के परिजन उचित जांच की मांग कर रहे हैं।

उज्जवल बटाविया ने युद्ध जेट विमान L39NG, अल्बेट्रोस से भरी उड़ान



छिंदवाड़ा।उज्जवल बटाविया, छिंदवाड़ा के निवासी, नौजवान और ऊर्जवान, ने आज एक और अत्याधुनिक अदभुत काम किया है। लटविया की राजधानी वेगाम में बेल 39 हब अल्बेट्रोस युद्ध जेट विमान को उड़वाया। उज्जवल, जो कि वर्तमान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जर्मनी में एक स्टार्टअप के मालिक भी हैं, यह उनका जुनून है जिसने उन्हें इस दिशा में अग्रसर किया है। उन्होंने जर्मनी में अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त किया और स्कायडाइविंग, बंजी जॉिंग, क्लिफ जॉिंग जैसे कई साहसिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अब तक 33

देशों की यात्रा की है। उनका यह साहसिक और उत्साही जीवन छिंदवाड़ा के कुछ युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। यह उज्जवल की प्रेरणादायक खबर है, जो अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनकी उड़ान, उनकी जुनून और उनकी साहसिकता हर किसी के मन में नये सपनों को जगाने की प्रेरणा भर रही है। यह एक सच्चा उदाहरण है कि जब मुनघुप में संकल्प होता है तो वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। इस खबर का संक्षेप तो यह है कि काम के साथ-साथ अपने सपनों को जीने पर भी ध्यान देना चाहिए। उज्जवल ने वास्तव में सबित किया है कि साहस, जुनून और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि जीवन में सिर्फ काम ही नहीं, अपने सपनों को जीने पर भी ध्यान देना चाहिए।

पूरे प्रदेश में मची है त्राहि-त्राहि भाजपा लूट रही है वाहवाही

जिला कांग्रेस कमेटी का धरना-प्रदर्शन आज: ओक्टे

छिन्दवाड़ा। जिला सहित सम्पूर्ण प्रदेश में हर दिन बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के साथ किसानों की समस्या तथा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के आसामान छूने को लेकर कांग्रेस का प्रादेशिक व जिला स्तरीय विरोध सतत जारी है। इन समस्याओं के अतिरिक्त भाजपा सरकार ने अपनी अनदेखी के चलते अनेकों मानव निर्मित समस्यायें प्रदेश की जनता पर थोप दी है। जनसामान्य द्वारा विरोध किये जाने के बाद भी सत्ता के मद में डूबी भाजपा सरकार केवल झूठे परोसने में लगी हुई है। समस्याओं से घिरी जनता जहां एक ओर त्राही-त्राहि कर रही है वहीं दूसरी ओर भाजपा महाजनसम्पर्क अभियान चलाकर झूठी वाह-वाही लट्टने का प्रयास कर रही है।

विज्ञप्ति के माध्यम से उक्त उद्गार व्यक्त करते हुये जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा



नरेन्द्र मोदी द्वारा उज्जैन में सप्तऋषियों की मूर्ती का अनावरण करना और हल्की आंधी में इन मूर्तियों का गिरकर टूटकर बिखरना न केवल अपशगुन है बल्कि यह महालोक निर्माण में किये गये महा भ्रष्टाचार का उदाहरण है जिसकी गहन जांच जरूरी है और ऐसे ही भ्रष्टाचारों की शिकायत और उनकी जांच के प्रपत्र जिस सतपट्टा भवन में विभिन्न फाइलों में संग्रहित थे वहां पर आग लगना या लगाना भी एक जांच का विषय है ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके। श्री ओक्टे ने आगे कहा कि जिस प्रदेश में ना भगवान का घर सुरक्षित है और ना सरकार का घर अर्थात सचिवालय सुरक्षित है ना ही अस्पतालों में बिजली उपलब्ध है और न ही बहु, बेटीयां सुरक्षित है ऐसे क्षत विश्वत माहौल में जनता कैसे जीवन निर्वेहन कर रही है। यह एक विचारणीय विषय है राजजीव कांग्रेस भवन से एक रैली के रूप में जिलाध्यक्ष कार्यालय के लिये प्रस्थान करेगी।



ऐतिहासिक हुआ महरौनी में पंचकल्याणक महोत्सव

छिन्दवाड़ा सहित पूरे देश से पधारे जैन बंधु

छिन्दवाड़ा / महरौनी - उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी ललितपुर के महरौनी नगर में भक्त से भगवान बनने की कला सिखाने वाला जैनदर्शन का सर्वोत्कृष्ट उत्सव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा



महोत्सव 19 से 23 जून तक विविध उपलब्धियों सहित ऐतिहासिक रूप से साआनन्द सम्पन्न हुआ जिसकी भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की सकल जैन समाज ने सराहना की। यह मांगल महोत्सव गुरुदेवश्री के पुण्य प्रभावना योग में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के निर्देशन में श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट महरौनी, मुमुक्षु मण्डल टीकमगढ़ एवं बानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।

महोत्सव के मौडिया प्रभारी दीपकराज जैन ने बताया कि पांच दिवसीय श्री 1008 नेमिनाथ दिगम्बर जिनबिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी पण्डितश्री अभिनन्दनजी शास्त्री खनियाथनार के प्रतिष्ठाचार्यत्व में सम्पन्न हुआ जिसमें तीन लोक के नाथ

तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का क्रमशः गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्षकल्याणक महोत्सव मनाकर मनोहारी जिनबिम्बों की प्रतिष्ठा कर श्री महावीर स्वामी दिगम्बर जिनालावरी के मनोहारी वेदी पर विराजमान किया गया।

अति सुंदर जिनालय में पावन चरण श्री गिराजमान किये गए साथ ज्ञायक भगवान आत्मा की गुंज के साथ तू स्वयं भगवान है ऐसा बताने वाला स्वाध्याय भवन एवं शाश्वत तीर्थराज सम्मोदशिखरजी की मनोहारी रचना कर भगवत्तों के पावन चरण विराजमान किये गए जिसे सम्पादित करने का सौभाग्य श्रीमती कुसुम विमलकुमार जैन नीरू केमिकलस् दिल्ली एवं श्रीमती सुनीता प्रेमचंद बजाज परिवार मुमुक्षु आश्रम कोटा को एवं मुख्य शिखर का निर्माण नवीन भाई केशवलाल मेहता परिवार मुम्बई, मणिभाई कारिया परिवार द्वारा मुख्य शिखर निर्माण एवं ध्वज स्थापना का सौभाग्य श्री वासन्ती बेन शाह परिवार मुम्बई को प्राप्त हुआ।

25 को भोपाल में आउटसोर्स महासम्मेलन, जिले से 500 कर्मचारी होंगे शामिल

छिंदवाड़ा। मप्र आउटसोर्स, अस्थाई एवं सविदा कर्मचारी कांग्रेस के आन्धान पर प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में 25 जून को भोपाल में पहली बार सभी विभागों के आउटसोर्स, अस्थाई कर्मचारी महासम्मेलन में एक मंच पर आकर शिखराज सरकार द्वारा सरकारी विभागों में लागू किए गए अन्याय कारी आउटसोर्स कल्चर को समाप्त करने के संघर्ष का शंखनाद करेंगे। महासम्मेलन में प्रदेश से सभी विभागों के 10 हजार से अधिक आउटसोर्स, अस्थाई कर्मचारी हिस्सा लेंगे। महासम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथजी को मुम्बई, मणिभाई कारिया परिवार द्वारा मुख्य शिखर निर्माण एवं ध्वज स्थापना का सौभाग्य श्री वासन्ती बेन शाह परिवार मुम्बई को प्राप्त हुआ।

मप्र राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम चंदनगांव छिन्दवाड़ा में सोयाबीन के उन्नत किस्मों का बीज उपलब्ध
 छिन्दवाड़ा। उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सोयाबीन की उन्नत किस्म जे.एस.-2098 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। यह किस्म हल्की सोयाबीन एवं भारी जमीन में अधिक उत्पादन देती है। सोयाबीन फसल किस्म जे.एस.-2098 के अलावा अन्य किस्म आर.व्ही.एस.-2002-4 आदि का प्रमाणित बीज मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम चंदनगांव छिन्दवाड़ा में 8 हजार 950 रुपये प्रति किंटल की दर पर उपलब्ध है।

महिला सशक्तिकरण के लिये परिवहन भी एक महत्वपूर्ण घटक है: कलेक्टर
अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिये निःशुल्क ड्रायविंग ट्रेनिंग का शुभारंभ



छिन्दवाड़ा। राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिये 21 दिवसीय निःशुल्क ड्रायविंग ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा आज अशोक लिलैंड इंस्टीट्यूट फॉर ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, छिंदवाड़ा में निःशुल्क ड्रायविंग ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम 17 जुलाई तक चलेगा।कलेक्टर श्रीमती पटले ने कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कहा कि आज जब महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो महिलाओं को पढ़ाने और उनके रोजगार के प्रबंधन के बारे में सोचा जाता है, जबकि महिला सशक्तिकरण के लिये परिवहन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जब भी किसी महिला को घर से बाहर किसी कार्य के लिये जाना होता है तो आज भी उन्हें घर के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज का यह कार्यक्रम न सिर्फ चर्यामित्र प्रशिक्षु महिलाओं को परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनायेगा बल्कि, इनसे प्रेरणा लेकर अन्य महिलायें भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती पटले ने अशोक लिलैंड इंस्टीट्यूट फॉर ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, छिंदवाड़ा म.प्र. के प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की।

इस कार्यक्रम का आयोजन कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनपुरिया द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिये ड्रायविंग ट्रेनिंग का यह कार्यक्रम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रथम बार छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रशिक्षुओं को कोर्स पूर्ण करने पर प्रमाण-पत्र के साथ ही ड्रायविंग लायसेंस बनाकर दिया जायेगा। इससे उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस ड्रायविंग लायसेंस को प्राप्त करने पर उन्हें टेक्ससी कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस आदि चलाने की पात्रता होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रशिक्षु महिलाओं को ट्रेनिंग संस्थान में निःशुल्क भोजन एवं रूकने की व्यवस्था भी रहेगी। इस दौरान अशोक लिलैंड इंस्टीट्यूट फॉर ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, छिंदवाड़ा म.प्र. के डायरेक्टर श्री सुनील देशपांडे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रोहन दुबे द्वारा किया गया।

मेडिकल कॉलेज को डॉ.अम्बेडकर का नाम दियाजावे, सौपा ज्ञापन
 छिन्दवाड़ा। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा पर छिन्दवाड़ा पथारे बैतूल सांसद श्री दुर्गादास उडके को भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश सचिव(दक्षिण)एड.रमेश लोखंडे,साहित्यकार एस.आर.शेंडे,जिला उपाध्यक्ष एड.राजेश सांगोडे ,मनोहर नारनवरे सहित प्रतिनिधि मंडल ने वर्षों से लंबित छिन्दवाड़ा मेडिकल कॉलेज को डॉ.बाबासाहब भीमराव अंबेडकर का नाम दिए जाने हेतु मांग पत्र सौंपा। उल्लेखनीय है कि,मेडिकल कॉलेज को संविधान निर्माता का नाम दिए जाने हेतु प्रारंभ से अनेक अम्बेडकरी संगठनों द्वारा मांग की जाती रही है ,जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी,तत्कालीन जिला पालक मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने बाबासाहब का नाम देने की सार्वजनिक घोषणा की थी।वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने भी मेडिकल कॉलेज को बाबासाहब का नाम देने संबंध प्रस्ताव कैबिनेट से रखने का आश्वासन दिया था। एड.रमेश लोखंडे ने बताया कि,दुर्भाग्य से छिन्दवाड़ा जिले में किसी भी शासकीय संस्थान को आजतक भारतीय संविधान के शिल्पकार विश्व के महान विद्वान डॉ.बाबासाहब का नाम नहीं दिया गया है,जबकि जिले में स्थित कई संस्थानों को विभिन्न महापुरुषों के नामों से अलंकृत किया गया है । प्रतिनिधि मंडल में शामिल भारतीय बौद्ध महासभा के जिला सचिव एस.आर.बेले,जिला संगठक वसंता सोमकुंवर,सचिव ममता सहारे,उपाध्यक्ष सुनीता निकोसे , ने आगाह किया कि,मेडिकल कॉलेज छिन्दवाड़ा को डॉ.अम्बेडकर जी का नाम देने की शासन शीघ्रता से पहल करे,अन्यथा भविष्य में जन आंदोलन किया जाएगा।



मुख्यमंत्री के साथ कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मभूषण डॉ. आडवाणी तथा लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने किया पौधरोपण



भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में नीम, बादाम और जामुन के पौधे रोपे। प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मभूषण व पद्मश्री डॉ. सुरेश एच. आडवाणी, सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, फिल्म निर्देशक-अभिनेता-संगीत निर्देशक और गीतकार पीयूष मिश्रा, जादूगर आनंद, जीवा आयुर्वेद के संचालक डॉ. विकास चौहान, संगीतकार श्रीमती कविता सेठ, पार्श्व गायिका और गीतकार सुश्री श्रद्धा पंडित, कवि अमन अक्षर पौधरोपण में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि अपने-अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित यह व्यक्तिव मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पधारे हैं। मुख्यमंत्री चौहान के साथ बी.बी. नायडू, निखिल मेथिया, गौरव तिवारी, डॉ. अरविंद पाण्डेय, कर्नल एच.आर. रोहिल और सुश्री दिशा तिवारी ने भी पौधे रोपे।

फर्जी अनुदान स्वीकृति प्रकरण में खाद्य मंत्री द्वारा एफआईआर के निर्देश

भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के फर्जी लैटर हेड और हस्ताक्षर से मंत्री की स्वेच्छानुदान निधि से 40-40 हजार रुपये की राशि स्वीकृति के प्रकरण में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्री सिंह ने अनुपपुर पुलिस अधीक्षक को पत्र में लिखा है कि उनके लैटर हेड पर उनके फर्जी हस्ताक्षर से कूटरचना कर शासकीय धन के गबन के उद्देश्य से 3 लोगों के नाम मंत्री स्वेच्छानुदान निधि से 40-40 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।

कलेक्टर अनुपपुर ने 12 जून 2023 को प्राप्त इस फर्जी और कूटरचित पत्र के आधार पर नेक मोहम्मद आधार-283972723760, श्रीमती सोमरा आधार-302326654750 एवं सुशांत कुमार सेन आधार-538818272342 को उपचार के लिये 40-40 हजार रुपये स्वीकृत किये। मंत्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक अनुपपुर को शासकीय दस्तावेज के आधार पर शासकीय राशि के गबन के लिये कूटरचित षड्यंत्र के दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सभी नगरीय निकायों में होगा आयुष्मान कार्ड वितरण

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगामी 27 जून को शहडोल में आयुष्मान कार्ड वितरण और सिकल सेल ऐनीमिया उन्मूलन मिशन-2047 का शुभारंभ किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी आयोजित किया जायेगा। साथ ही प्रधानमंत्री के शहडोल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण निकायों में किया जायेगा।

कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आशा-उषा कार्यकर्ता घर-घर जाकर नगरिकों को निकाय की ओर से कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगी। कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जायेगी और हितग्राहियों को कार्ड वितरित किये जायेंगे। वहीं आयुष्मान कार्ड बनाने की विधि के बारे में भी समझाया जायेगा। कार्यक्रम में योजना के हितग्राही मंच से अपने अनुभव साझा करेंगे।

नगरीय निकायों को क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर आयुष्मान भारत हितग्राहियों के नामों की सूची चप्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जिले में प्रभावी कार्यक्रम आयोजित करने वाले 3 नगरीय निकायों को जिला स्तर पर प्रशंसित किया जायेगा।

डिप्टी कलेक्टर ने कहा- हर दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किया

भोपाल। बैतूल जिले के आमला की रहने वाली डिप्टी कलेक्टर और छतरपुर के लवकुश नगर एसडीएम निशा बांगरे ने गुरवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को त्यागपत्र भेज दिया है। अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन के आयोजन और अपने इस्तीफे को लेकर एक बार फिर से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे सुर्खियों में हैं।

उन्होंने अब कभी प्रशासनिक सेवा में नहीं लौटने का संकल्प दोहराते हुए आमला में होने वाले आयोजन को षड्यंत्र का शिकार होने की बात भी कही है। निशा ने इसके लिए सीधे-सीधे जिले के मुखिया और एक माननीय को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे राजनीतिक कारणों को भी खारिज कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर बांगरे ने डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा एक साथ पास की थी, लेकिन एक साथी प्रतियोगी के कहने पर उन्होंने डीएसपी का पद छोड़ दिया था। डिप्टी कलेक्टर बन गई थीं।

मुख्यमंत्री ने की घोषणा मप्र के कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन में 4 प्रतिशत डीए की वृद्धि

भोपाल। प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता शीघ्र ही मिलने लगेगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह जिले सीहोर की भैरंदा तहसील के गिहन्नौर ग्राम में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का अंतर है। अब इसे समाप्त किया जाएगा। रोजगार सहायकों की समस्या के समाधान को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया।

इसके लागू होने पर कर्मचारियों को 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सीएम की घोषणा से कर्मचारियों को हर महीने प्रथम श्रेणी अधिकारियों को न्यूनतम 16 सौ से 6 हजार तक का लाभ होगा। जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दे सकता है।



कर्मचारी संगठन लंबे समय महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार जनवरी 2023 से कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। जबकि, प्रदेश के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। अब मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश के 25 हजार पेंशनरों को फायदा होगा। शिवराज सरकार ने प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ- बता दें, चुनावी साल में प्रदेश के कर्मचारी संगठन अलग-अलग मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते रहे हैं और आंदोलन भी करते रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और करीब तीन लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।



मानसरोवर संस्थान के तत्वावधान में कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राएं और अतिथि भारतीय वेशभूषा में शामिल हुए।

उज्जैन के सिद्धाश्रम घाट पर स्नान करने पर रोक



उज्जैन। शिप्रा नदी में डूबने से बीते 10 दिनों में हुई 12 लोगों की लोगों की मौत के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शुक्रवार को रामघाट, नर्सिंह घाट, सिद्धाश्रम घाट, भूछी माता घाट पर सुरक्षा इंतजाम जांचने पहुंचे। उन्होंने जनसुख्खा के महेनजर नदी का जल स्तर कम करने, घाट पर सैप्टी चैन लगाने, लाइफ जैकेट की संख्या बढ़ाने और स्नान कर रहे लोगों को बार-बार सिटी बजाकर चेतावनी देने के निर्देश दिए।

होमगार्ड कमांडेंट संतोषकुमार जाट ने उन्हें बताया कि सिद्धाश्रम घाट पर सबसे ज्यादा डूबने की घटनाएं होती हैं। इस पर कलेक्टर ने यहां स्नान पर रोक लगाने, घाट पर परमानेंट बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि कोई प्रतिबंध के बावजूद स्नान करने आए तो उससे जुर्माना

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में परिवहन सहित नौ विभागों को ए ग्रेड

भोपाल। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में परिवहन विभाग सहित नौ विभागों को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। 10 विभागों को बी ग्रेड और नौ विभागों को सी ग्रेड मिला है। मई माह की ग्रेडिंग में ए ग्रेड वाले विभागों में परिवहन विभाग का वेटेज स्कोलर 88.84 प्रतिशत रहा है।

इसी तरह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ऊर्जा, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास, पशुपालन एवं डेयरी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ए ग्रेड में रहे।

मई माह में सर्वाधिक शिकायतें बिजली संबंधी रही। ऊर्जा विभाग की 64,621 शिकायतें की गईं। इसी तरह नगरीय विकास एवं आवास विभाग की 44,312 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

शिकायतों के निराकरण में नौ विभागों को सी ग्रेड- पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, वन, अनुसूचित जाति कल्याण, जल संसाधन, जनजातीय कार्य, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की रैंकिंग में सी ग्रेड में रहे।



ए ग्रेड प्राप्त विभाग			
विभाग	शिकायतें	वेटेज	स्कोर
परिवहन	6107	88.84	
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	34031	87.67	
ऊजा	64621	87.01	
गृह	35017	85.93	
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	43351	85.49	
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	5957	83.08	
नगरीय विकास एवं आवास	44312	83.02	
पशुपालन एवं डेयरी	1541	81.38	
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	25435	80.26	

सीईओ, एडीएम और एसडीएम संभालेंगे प्रधानमंत्री दौरे की जिम्मेदारी

भोपाल। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एवं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ, एडीएम, एसडीएम सहित दो दर्जन से अधिक अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को बैठक लेकर रूपरेखा तैयार की है। कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर समन्वय अधिकारी की भूमिका जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह, एसडीएम आकाश श्रीवास्तव, क्षितिज शर्मा, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आदित्य जांगेला और नायब तहसीलदार सोनिया परिहार निभाएंगी। इसी तरह सहायक समन्वय अधिकारी की भूमिका एसडीएम मनोज वर्मा निभाएंगे। राजाभोज विमानतल का प्रभार एडीएम हरेंद्र नारायण और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था की जिम्मेदारी एसडीएम जमील खान को सौंपी गई है।

राजस्व अफसरों की वर्किंग में बड़े बदलाव की तैयारी, तहसीलदारों कार्यक्षेत्र बढ़ेंगे

भोपाल। प्रदेश में तहसीलदारों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है लेकिन उनके अधिकार कार्यक्षेत्र बढ़ने के बाद कम हो जाएंगे। राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में फैसला ले सकती है। सरकार के पास पहुंची बदलाव की अनुशंसा में कहा गया है कि प्रदेश में किसी भी तहसील में पदस्थ तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार का कार्यक्षेत्र संपूर्ण तहसील की जा सकती है। उन्हें किसी क्षेत्र विशेष या सर्किल के कार्यक्षेत्र से मुक्त किया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी राजस्व न्यायालय में तहसीलदार नहीं है तो आम जन का काम प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए तहसील में आने वाले केस नम्बर के आधार पर तहसील न्यायालय के नाम तय किए जाएं और तहसीलदार के क्षेत्राधिकार बढ़ें तो इसका असर रेवेन्यू कोर्ट आने वाले लोगों के केस पर न पड़े।

राज्य भूमि सुधार आयोग ने किसानों और आमजन की परेशानों कम करने के लिए इस तरह के बदलाव की अनुशंसा शासन से की है। इसके बाद प्रदेश में तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव हो सकता है। आयोग की अनुशंसा में साफ कहा गया है कि तहसील न्यायालयों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें किसी क्षेत्र विशेष में बांधकर न रखा जाए। आयोग ने कहा है कि राजस्व न्यायालयों के क्षेत्रों को राजस्व निरीक्षक सर्किल वार या पटवारी हल्का या सेक्टरवार बांटें और तहसील न्यायालय पदाधिकारी के नाम से संचालित करने की प्रक्रिया समाप्त की जानी चाहिए। इसके स्थान पर हर तहसील के लिए न्यायालयों की संख्या तहसील में वर्ष के दौरान दर्ज होने वाले अनुमानित प्रकरणों के भार के आधार पर निर्धारित कर शासन स्तर से इसका नोटिफिकेशन किया जाना चाहिए। इन सभी न्यायालयों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण तहसील रखा जाए ताकि राजस्व प्रकरण तहसील के किसी भी न्यायालय में निबट सके और अधिकारी की पदस्थापना में परिवर्तन से आमजन के लिए भ्रम पूर्ण स्थिति न बने। कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालयों को क्रमांक देकर संचालित करने की व्यवस्था लागू की जाए। इससे तहसील में पदस्थ भारसाधक तहसीलदार के राजस्व न्यायालय को न्यायालय तहसीलदार क्रमांक एक के आधार पर बताकर तहसील और जिला नाम दिया जाए। इसी तरह तहसील में भारसाधक तहसीलदार के अतिरिक्त पदस्थ अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के राजस्व न्यायालय को यथास्थिति न्यायालय तहसीलदार क्रमांक दो, क्रमांक तीन और इसी तरह अन्य क्रमांक दिए जाएं।

पेज 1 का शेष

अवेध भूजल निष्कर्षण पर कार्रवाई, मंत्रालय के महत्वपूर्ण निर्देश जारी

सलाहकार विभाग के नाम पर भी उद्योगपतियों से ज्यादा पैसे की मांग करते हैं। इस विषय पर केंद्रीय भूजल मंडल भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक ए.के. बिस्वाल का साफ कहना है कि भूजल की एनओसी हेतु सिर्फ निर्धारित फीस ही मान्य है उसके अलावा कोई राशि मान्य नहीं है। भले अभी एनओसी की प्रक्रिया धीमी है, मगर इसके शुरू होने से उत्साहजनक नतीजे भी दिखने हो गए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण और विभिन्न पहलुओं पर निर्देश - ग्राऊंड, वाटर पर किए गए अध्ययन, संकलित डाटा और आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार वर्ष 2021 में ओपन आई न्यूज द्वारा प्रेषित, प्रस्तुतिकरण पर सबसे महत्वपूर्ण और उत्साहजनक परिणाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र फरवरी 2023 के रूप में सामने आए हैं। मंत्रालय के इस पत्र, जिसे मप्र स्टेट एनवायरनमेंट असेसमेंट अथॉर्टी (सिआ) प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग मप्र तथा क्षेत्रीय निदेशक सेंट्रल ग्राऊंडवॉटर बोर्ड को भेजा गया है, का सार एकदम स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि बिना सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्ड की पूर्व अनुमति के उद्योगों (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेसीडेंशल/ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, सीबी डब्ल्यूटी इत्यादि) को ग्राऊंड वॉटर निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इन उद्योगों को उनके द्वारा प्राप्त की गई ग्राऊंड वॉटर की एनओसी की प्रतियां सभी नियामक प्राधिकरणों (रेग्युलेटरी अथॉर्टी) में जमा की जाएगी। ये प्राधिकरण सिआ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल, मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सभी प्रोजेक्ट अथॉर्टीज इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा ग्राऊंड वॉटर की एनओसी में वर्णित शर्तों का आवश्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। और इस का अनुपालन की अद्यतन स्थिति (इस्टेटस) को छमाही अनुपालन प्रतिवेदन (कम्प्लायंस रिपोर्ट) के रूप में जमा किया जाएगा। सिआ ने इस बाबद एक ऑफिस मेमोरेन्डम जारी कर दिया है।

अब नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए- देखा जाए तो ओपन आई न्यूज के चार वर्षीय प्रयास को मूर्तरूप दिया जा चुका है। पर्यावरण वन मंत्रालय जोकि इस विभाग का शीर्षस्थ विभाग है, ने अब स्पष्ट रूप से भूजल को लेकर समुचित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब उसके अधीनस्थ गठित विभागों जैसे सिआ, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, केंद्रीय भूजल मंडल की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे भूजल हेतु जारी भारत के राजपत्र दि. 24.09.2020 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी उद्योगों में उपयोग होने वाले भूजल के संरक्षण, की दिशा में समुचित प्रयास करते हुए नियमों का पालन एनओसी करवाएं। भारत शासन ने भूजल लेने हेतु सभी को उचित समय सीमा दे दी है। अगर इसके बाद भी जो उद्योग और संस्थान भूजल की एनओसी नहीं लेते हैं उन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कम से कम ऐसे पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली तो जरूर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हमारी प्राकृतिक संसाधनों का अवैध तरीकों से दोहन करते आ रहे हैं। ये तरीका जारी रहा तो हमारी धरती में मौजूद भूजल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और हमारी भावी पीढ़ी पानी के अभाव से रूबरू होगी।